जनवरी: 2025 वर्ष: 10 अंक: 1

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

अंदाज - ए - लखनऊ

श्रद्धांजलि

शुल्क: 50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारा समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

संपादकीय सलाहकार मंडल

डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक

प्रो प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक

डॉ सतीश मिश्रा

सहयोगी संपादक

प्रो शिवाजी सरकार

विशेष प्रतिनिधि

राजीव माथुर

लखनऊ संवादाता

ज़ेबा हसन

पटना संवादाता

अजय यायावर

रायपुर संवादाता

संदीप कुमार सिंह

मुख्य सह-संपादक

प्रशांत गौतम

सह-संपादक

अंकुर कुमार

मुख्य प्रबंधक

जगदीश गौतम

विधि परामर्शदाता

संजय माथुर

पंजीकृत कार्यलय

2325, सेक्टर - डी, पॉकेट - 2, वसंतकुंज, नई दिल्ली

कार्यालय

69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014

दूरभाष - *9810385757 / 9910069262*

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-

editor@mediamap.co.in

संपादकीय		
पत्र पाठको के		
एक झलक पिछले अंक की		
विचार प्रवाह		
बीता वर्ष 2024 का		
लोकतांत्रिक विमर्श के वापसी की आशा लिए आया नया वर्ष	डॉ मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली	10
जनवरी 26: गणतंत्र दिवस पर विशेष		
संवैधानिक शासन के 75 साल बाद कहां हैं हम	प्रो राम पुनियानी	12
दिसंबर 6: पुण्यतिथि		
डॉ. अंबेडकर की दलित सबलीकरण की विरासत और भाजपा	विद्या भूषण रावत	14
आर्थिक जगत		
कॉर्पोरेट कार्यशैली में पारदर्शिता और जनहित की आवश्यकता	प्रो शिवाजी सरकार	16
अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य		
क्या अब अमेरिका और कनाडा में बसना एक दिवास्वप्न होगा	प्रभजोत सिंह	19
शिक्षा जगत		
सामाजिक-मानवीय आधार पर शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता	डॉ. अनिल कुमार रॉय	22
राज्यों से		
भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की प्रताड़ना भुगतते छात्र	डॉ. नीरज कुमार	25
भावभीनी श्रद्धांजलि		
साहसी निर्णय लेने वाला एक सौम्य व्यक्ति	प्रो प्रदीप माथुर	27
कथा साहित्य		
बुलंदी की पराकाष्ठा	दिनेश नारायण वर्मा	31
हास्य व्यंग		
नया साल शुभ हो : नए साल में हम नये छप्पर फाड़े	अनूप श्रीवास्तव	33
अंदाज़-ए-अवध		

नया वर्ष नयी चुनौतियां

नए वर्ष में बीते वर्ष की सफलताओं और असफलताओं का लेखा-जोखा करने के साथ-साथ आने वाले समय की चुनौतियों का आकलन करना भी आवश्यक होता है। इस तरह देखा जाए तो 2025 का यह वर्ष हमारे लिए तमाम चुनौतियां लेकर आया है। अब वह समय है जब हम आपसी झगड़ों, वाद-विवादों, आरोप और प्रत्यारोपों की संस्कृति से ऊपर उठकर एक सवस्थ दृष्टिकोण विकसित करें और अपने देश और समाज को नई दिशा दें। इसके लिए आवश्यक है कि हम झूठे प्रचार, आत्मप्रशंसा और अपने गुणगान की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर वस्तुस्थिति को देखने-समझने का साहस करें और सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें।

वास्तिकता यह है कि विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का दावा करने और अपने आपको विश्वगुरु का पदक देने के बाद भी तमाम देशों की तुलना में हमारी विकास की गति बहुत धीमी है। दो कारणों से हमें अपने देश के तीव्र विकास का भ्रम होता है। एक है बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण, विश्व के अन्य देशों की व्यापारिक दृष्टि में हमारा बड़ा बाजार होना, दूसरा है हमारी जनसंख्या के ऊपर के लगभग 15% लोगों के हाथ में देश का धन संचित होना। इस वर्ग का जीवन स्तर विश्व के किसी भी विकसित देश के नागरिकों के समान है या बेहतर है। हमारी जनसंख्या के इस 15% वर्ग का अर्थ है लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या, जो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप की पूरी जनसंख्या के लगभग बराबर है। इससे यह भ्रम होता है कि हमारा देश वास्तव में विश्व के विकासशील देशों के समकक्ष आ गया है।

परंतु कटु सत्य यह है कि हमारे देश के 80 करोड़ लोग, जिनकी जनसंख्या पूरे यूरोप महाद्वीप (74.5 करोड़) या उत्तर अमेरिका महाद्वीप (61 करोड़) से भी अधिक है, आज भी सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त राशन पर आश्रित हैं। यदि हमें देश का समग्र विकास करना है तो उसके लिए झूठे प्रचार और आत्मप्रशंसा की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर हमें देश की इस बड़ी वंचित श्रेणी के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास करने होंगे। इस वर्ष जब हमारे देश में गणतंत्रात्मक प्रशासन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमें गंभीर चिंतन कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है।

पिछला वर्ष जाते-जाते भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु में हमारे देश को एक गंभीर आघात दे गया। आज हमें अपने देश के राजनीतिक वातावरण को स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए उनकी जैसी विनम्रता, सादगी और ईमानदारी वाले नेतृत्व की आवश्यकता है।

आज देश में सांप्रदायिकता तथा आपसी भेदभाव समाप्त करने के लिए जिस संस्कृति की आवश्यकता है, उसे हम उत्तर भारत में गंगा-जमनी तहजीब कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा की भावना को बल देने के लिए हम आपकी इस पत्रिका में गंगा-जमनी तहजीब के क्षेत्र अवध और उसके सरताज लखनऊ की जीवनशैली पर इस अंक से एक विशेष परिशिष्ट प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है कि यह आपके स्वागत योग्य होगा।

~प्रो प्रदीप माथुर

****

बदल रहा है देश का सियासी मिजाज !

हमारे देश की सियासत का मिजाज पिछले कुछ समय से इतना अधिक बदल गया है जिसकी कल्पना ना तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने ना ही आम आदमी ने कभी की थी। कुछ प्रश्न आज देश के चिंतनशील व्यक्तियों को चिंता में डाल रहे हैं और उन्हें इस बदले सियासी मिजाज से जो पीड़ा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से सत्ता और विपक्ष के बीच छिड़ा सियासी द्वंद बढ़ते-बढ़ते वहां तक पहुंच गया जो एक प्रतिशोध में बदलता हुआ अश्लील भाषा के आरोप-प्रत्यारोप के साथ गाली-गलौच और फिर अब संसद के गलियारे में आपसी हाथापाई और धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। लोकसभा और राज्यसभा के पिछले कई सत्र देश की जनता के हित में कोई बड़ा फैसला लिये बिना शोर शराबे के बीच समाप्त हो गए और अब मौजूदा शीतकालीन सत्र जो 26 नवंबर को शुरू हुआ और बीस

दिसंबर को समाप्त हो गया। इसमें भी हो-हल्ला और शोर शराबा ही होता रहा। इस सत्र की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि हमने देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दो दिन की बहस लोकसभा में और दो दिन की बहस राज्यसभा में कराने का निर्णय लिया। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर छिड़ी बहस चार दिन चली जरूर लेकिन इस दौरान भी हमारे सियासी नेताओं ने अपने चिर परिचित आचरण का वही पुराना परिचय देते हुए संविधान की कई बार धज्जियां खुलकर उड़ाई। इसी बीच राज्यसभा की बहस के अंतिम दिन अंतिम वक्ता के रूप में बोलते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर लगाए गए कई आरोपों के बीच अपने विचारों को समाहित करते हुए संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल दिये जो स्वर्गीय डा. बीआर अंबेडकर के सम्मान में अपमानजनक भी थे। विपक्ष ने गृहमंत्री के उन शब्दों को पकड़ लिया और उन्हें डा. अंबेडकर के खिलाफ बोलने पर माफी मांगने को कहा और माफी ना मांगने पर देश के प्रधानमंत्री से गृहमंत्री को निष्कासित करने की अपील भी की। अमित शाह के ये शब्द विपक्ष ने पकड़कर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की कवायद शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख और मीडिया में बन रहे भाजपा विरोधी माहौल को बदलने के प्रयास में संसद भवन परिसर के अंदर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे देश के लोगों का ध्यान विपक्ष के उस विरोधी मुद्दे से भटक जाए। विपक्षी दलों का आरोप है कि अगले दिन जब वो अंबेडकर की प्रतिमा से अपना विरोध प्रकट करते हुए संसद परिसर में मुखर द्वार तक पहुंचे तो भाजपा के सांसदों ने उनका रास्ता रोका और उनके साथ धक्का- मुक्की की। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसदों का आरोप है कि वो विपक्षी सांसदों के डा. अंबेडकर को लेकर चलाए जा रहे झूठे अभियान पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए संसद की गैलरी में नारेबाजी कर रहे थे तो विपक्षी दल के सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन पर प्रतिक्रिया की और उनके साथ धक्का-मुक्की की जिससे उनके दो सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। अब किसने किसके साथ किस अंदाज में कितनी ताकत से कितनी धक्का-मुक्की की, इसकी कोई वीडियो फुटेज अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लोकसभा और राज्यसभा शांति के माहौल में चले और देश की समस्याओं का हल निकाले, ऐसा करवाना सत्ता दल का सबसे बड़ा दायित्व है। ~ ***कमल सेखरी***

सादगी की प्रतिमूर्ति: लाल बहादुर शास्त्री

लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना ने उन्हें देशवासियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उनकी विनम्रता से लोग महसूस करते थे कि वह किसी बड़े नेता नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति हैं जो देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जब देश में अनाज की कमी थी, शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया, जो किसानों और जवानों के साथ-साथ युवाओं को भी प्रेरित करता था। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी पर विश्वास जताया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यही देश को आगे ले जाएंगे।

शास्त्री जी का आदर्श वाक्य गुरु नानक जी से प्रेरित था, जिसमें उन्होंने जीवन में सादगी और दृढ़ता की बात की थी। वह हमेशा कहते थे कि असली सेवा उस पौधे की तरह होनी चाहिए, जो सदा हरा रहता है। शास्त्री जी का सपना था कि देश में हरियाली फैले और लोग किसानी करें।

उनकी सच्चाई और समर्पण ने उन्हें महान बना दिया। उनका मानना था कि एक सच बोलना आसान होता है, जबकि झूठ से कई और झूठ पैदा होते हैं। शास्त्री जी के विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और सेवा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। ***~प्रशांत गौतम***

आर्थिक संकट का साया

डालर के मुकाबल रुपए का कामत गिर कर पचासी से अधिक हो गई। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपनी नीतियों में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है। कोरोना के बाद दुनिया के तमाम देश मंदी की चपेट में आ गए थे। उससे उबरने के लिए सभी ने अपने-अपने तरीके से उपाय किए। अमेरिकी फेडरल ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कर उसे साढ़े चार फीसद पर ला दिया है। इस तरह डालर की स्थिति मजबूत हुई है। फिर, जब से राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है, निवेशकों को लगने लगा है कि वहां निवेश करना सबसे फायदेमंद है। इसलिए बहुत सारे निवेशकों ने भारत से पैसे निकाल कर अमेरिका का रुख कर लिया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी छीजन दर्ज शुरू हो गई।

पिछले कुछ समय तक डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगभग रुकी हुई थी, तब विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार से डालर की निकासी करके रुपए की कीमत को रोक रखा है। मगर अब वह तरीका भी शायद काम नहीं आ रहा। डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट का असर व्यापार, पर्यटन, शिक्षा आदि पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकतर ईंधन तेल दूसरे देशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो सरकार का खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा, दवाइयों के लिए कच्चा माल, खाद्य तेल, इलेक्ट्रानिक साजो-सामान आदि के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। विदेश पढ़ने गए विद्यार्थियों और पर्यटकों की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए रुपए की कीमत का गिरना चिंताजनक होता है।

रुपए की कीमत गिरने की कुछ वजहें साफ हैं। व्यापार घाटा बढ़ता है, तो डालर के मुकाबले रुपए की कीमत घट जाती है। हालांकि वर्षों से निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, घरेलू बाजार और स्वदेशी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि निर्यात में लगातार कमी देखी जा रही है। व्यापार घाटा पाटने के लिए कई विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने और देसी वस्तुओं को प्रश्रय देने की कोशिश की गई, इसका कुछ असर भी हुआ। मगर फिर भी व्यापार घाटा कम नहीं हो पा रहा। खासकर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। महंगाई पर काबू पाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो दर को ऊंचा बनाए रखा है, मगर स्थिति यह है कि बाजार में पूंजी का अपेक्षित प्रवाह नहीं बन पा रहा। इसकी बड़ी वजह लोगों की आय में बढ़ोतरी न हो पाना है। इन स्थितियों का असर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पड़ता है। जैसे ही बाहरी निवेशकों को लगने लगता है कि किसी देश में उपभोक्ता व्यय घट रहा है, तो वे वहां निवेश करने से बचते हैं। पिछले कुछ समय से हमारी विकास दर और उसमें विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे में डालर की आवक कम हुई है। इस स्थिति में रुपए की कीमत घटनी शुरू हो जाती है। भारत में यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। सरकार अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डालर तक ले जाने को संकल्पित है, मगर रुपए की गिरावट का रुख देखते हुए इसका भरोसा नहीं बन पाता।

यह क्रिसमस कितना आनंदमय है?

दिसंबर 25, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, हर साल खुशियों और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने दोस्तों और परिवार को "मेरी क्रिसमस" कहते हैं। बच्चे सांता क्लॉज से उपहारों की उम्मीद करते हैं, और बड़े लोग केक और पार्टियों का आनंद लेते हैं। लेकिन इस साल का क्रिसमस भारत में क्या सच में उतना आनंदमय है?

भारत में 2024 में नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 745 घटनाएं दर्ज की गईं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) ने इस बढ़ती हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनाने की मांग की है। यूसीएफ के राष्ट्रीय समन्वयक ए.सी. माइकल ने कहा कि जैसे भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर कार्रवाई की थी, वैसे ही अब अपने देश में भी ईसाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

यूसीएफ ने देश के 12 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनका मानना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।

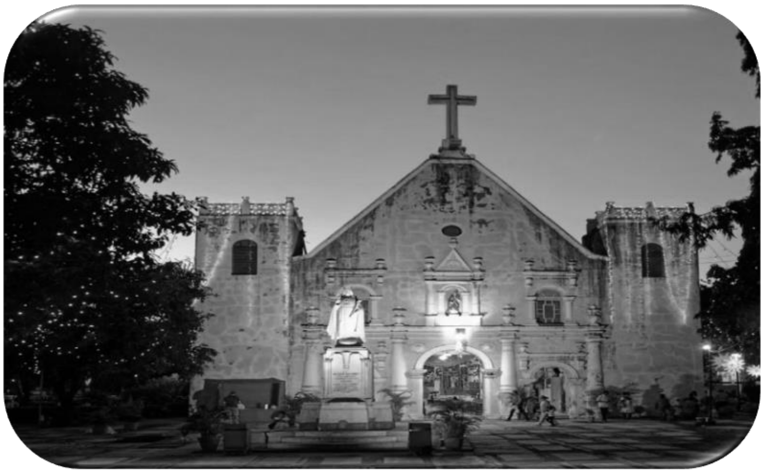

यूसीएफ हेल्पलाइन के अनुसार, 2014 से 2024 तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2023 में 734 घटनाएं दर्ज की गईं, और इस साल नवंबर तक यह संख्या 745 तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में हिंसा के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं।

यूसीएफ के अनुसार, मणिपुर में चर्चों पर हुए हमले और वहां की हिंसा के आंकड़े रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। 2023 में मणिपुर में हुई दुखद घटनाओं में 200 से अधिक चर्चों को ध्वस्त किया गया था।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कई मामलों में स्थानीय पुलिस हिंसा में शामिल रही है या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है।

यूसीएफ ने ईसाई समुदाय के राजनीतिक और सरकारी निकायों में प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि एंग्लो-इंडियन आरक्षण खत्म किया गया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पिछले पांच वर्षों से कोई ईसाई सदस्य नहीं है।

Uसीएफ ने 2015 में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की थी, जो संकटग्रस्त ईसाइयों को कानूनी मदद और सलाह प्रदान करती है। यह सेवा उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए बनाई गई थी।

क्रिसमस खुशी और शांति का प्रतीक है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या यह त्यौहार उनके लिए उतनी ही खुशी लेकर आता है जितनी कि इसके मायने हैं। ~ ***सैयद खलीक अहमद***

याद किये गए समाजवादी नेता मधु दण्डवते

126 विद्यालयों के 15 हजार छात्र छात्राओं ने की भागीदारी स्वाधीनता आंदोलन के सपनों को साकार करने के लिए गांधीजी की तरह का आचरण करना जरूरी: रमाशंकर सिंह

अगले वर्ष अहिंसा परमो धर्म विषय पर आयोजित की जाएगी प्रतियोगिताः अरुण श्रीवास्तव

मधु दण्डवते फाउण्डेशन द्वारा 'स्वाधीनता आन्दोलन और महात्मा गांधी' विषय पर आयोजित गोरखपुर जिला स्तरीय निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण चित्रगुप्त मन्दिर बख्शीपुर में किया गया। आयोजन में संपूर्ण वातावरण 'रघुपति राघव राजा राम' और 'वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे' जैसे गीतों के माध्यम से गांधीमय हो गया। इस अवसर पर 'मधु दण्डवते फाउण्डेशन के अध्यक्ष और इस समारोह के आयोजक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने स्वागत भाषण में मधु दण्डवते और महात्मा गांधी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। गांधी के विषय में यह निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने का मुख्य ध्येय यह है कि गांधी और गांधी के विचारों से विद्यार्थी परिचित हो सकें।

राष्ट्रपति ट्रंप की उल्टी पड़ती धमकियां

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा तैयार माल पर उच्च टैरिफ लगाने तथा ब्रिक्स देशों से अमेरिकी डॉलर में व्यापार जारी रखने तथा अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिकी मुद्रा में बनाए रखने के लिए कहने संबंधी हालिया बयानों का उल्टा असर हुआ है।इस संवेदनशील मुद्दे पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एकमत हैं। इस फोरम में शामिल होने वाले अन्य देशों में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और ईरान शामिल हैं।दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की नीति को चुनौती देने वाली पहली प्रतिक्रिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आई है। उन्होंने उद्घाटन समारोह के निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार

कर दिया है। बीजिंग ने कहा है कि जिनपिंग राष्ट्रपति ट्रंप के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इससे ट्रंप खेमे में हड़कंप मच गया होगा। यह समारोह 20 जनवरी, 2025 को होना है, यानी उस कार्यक्रम से छह सप्ताह पहले जिसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बजाय, बीजिंग ने कहा है कि उसके राजदूत अपने जीवनसाथी के साथ समारोह में शामिल होंगे।

ट्रम्प का यह बयान कि अगर कनाडा के लोगों को उच्च टैरिफ का असर महसूस होता है, तो कनाडा को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह शायद सिर्फ़ एक मज़ाक था, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने इसे पसंद नहीं किया। उत्तरी पड़ोसी ने हाल ही में यह बयान देकर जवाब दिया कि कनाडा अमेरिका को अपनी तेल आपूर्ति बंद कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी तटवर्ती राज्यों की अधिकांश ईंधन ज़रूरतें कनाडा से ईंधन आयात करके पूरी की जा रही हैं। इस प्रकार, कनाडा के अलग अस्तित्व का मुद्दा अब प्रबल राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ जुड़ जाएगा, जो शायद प्रधानमंत्री ट्रेड्यू के राजनीतिक करियर को फ़ायदा पहुँचाएगा। ***~गोपाल मिश्रा***

प्रखर विरोध के बीच सैटेनिक वर्सेज की वापसी

सलमान रुश्दी का विवादित उपन्यास, द सैटेनिक वर्सेज, 37 साल के प्रतिबंध के बाद भारत में फिर से प्रकाशित हुआ है, जिससे मुस्लिम समूहों में फिर से आक्रोश फैल गया है। कथित ईशनिंदा के लिए आलोचना की गई इस पुस्तक पर 1988 में सांप्रदायिक अशांति को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था।स्थिति तब और बिगड़ गई जब ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया, जिसके कारण लेखक को कई सालों तक छिपना पड़ा।

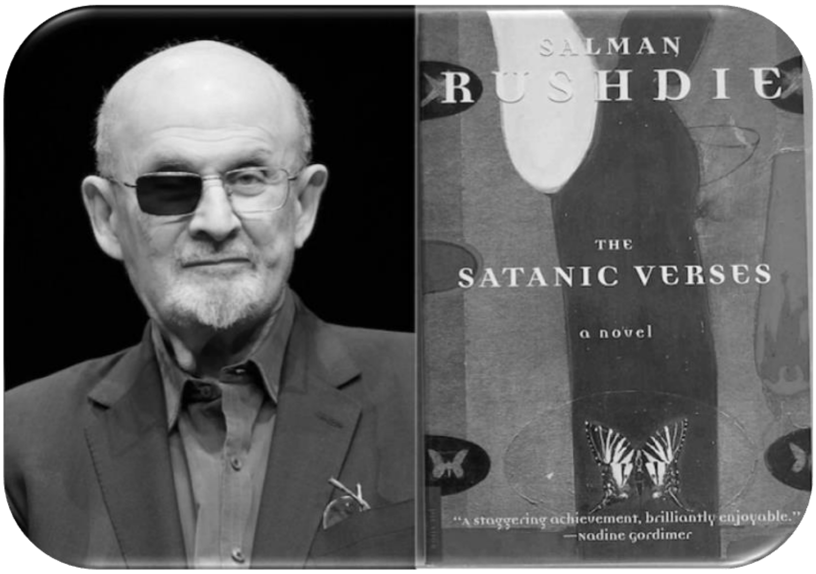

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद, जिसमें सरकार द्वारा मूल अधिसूचना प्रस्तुत न किए जाने का हवाला दिया गया था, कई किताबों की दुकानें उपन्यास को स्टॉक करने में हिचकिचाहट रखती हैं।

प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने इसकी बिक्री की निंदा की है, उनका तर्क है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है और इस्लामी मान्यताओं का अनादर होता है। यह विवाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जिससे ऐसे मामलों में सरकार की भविष्य की कार्रवाइयों पर सवाल उठते हैं।

****

बीता वर्ष 2024 का

लोकतांत्रिक विमर्श की वापसी की आशा लिए आया नया वर्ष

डॉ मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली

गया साल 2024 इतिहास का हिस्सा बन गया है। इस वर्ष को लोकतंत्र के लिए उम्मीद की नज़र से देखा जाएग। हालाँकि अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के लोग ने अपनी समस्याओं का समाधान दक्षिणपंथी विचारधारा में देखा है। वहीँ दुनिया भर से लोगों ने इजराइल की क्रूरता के खिलाफ आवाज भी उठाई। लम्बे संघर्ष के बाद सीरिया से तानाशाही का अंत हुआ, जनता के विरोध के कारण बांग्लादेश की निरंकुश शासक को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी वर्ष देश के मिजाज के विपरीत भारत में राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक द्वेष की रेखाएं उभरीं। इसी साल संविधान के 75 साल भी पूरे हुए और संविधान देश की राजनीति में मुद्दा बना। अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मंशा, लक्ष्य, और उद्देश्य साफ नजर आया।

पहली बार मोदी सत्ता ने खुलकर कहा कि देश में सिर्फ एक ही हिंदू पार्टी है और वह है भाजप। राम मंदिर उद्घाटन समारोह और नरेंद्र मोदी की पूजा पाठ में कॉर्पोरेट की भीड़, बॉलीवुड सितारों और बड़े व्यापारियों की उपस्थिति से मालूम हुआ कि सब कुछ सिमट रहा है। ऐसा प्रतीत होता था मानों चंद खिलाड़ी देश के संसाधनों और संपत्ति को अपने हाथ में लेने को आतुर हो। 2024 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने हर किला फतह कर लिया ह। उसकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकत। उस की राजनीतिक ताकत का मुकाबला कोई कर नहीं सकत। उसे कोई चुनौती दे नहीं सकता, वह जो चाहे कर सकती है। विपक्षी संसद सदस्यों को संसद से निलंबित कर दिया गया। एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष पर दबाव बनाया, पार्टियों को तोड़ा गया, उनके सदस्यों को भाजपा का हिस्सा बनाया गया। यहां तक कि जिन लोगों पर भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकती थी, उन्हें भी पार्टी में लाने से गुरेज़ नहीं किया गया। महज आरोपों के आधार पर दो राज्यों के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। उन्हें कथित आरोपों की बुनियाद पर खूब बदनाम किया गय। कहा गया कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएग। बिना किसी सबूत के कई महीनों तक जेल में रखा गय। आरोप साबित न होने के कारण कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिय।

> *2024 ने लोकतंत्र की उम्मीदों को भी जगाया और उसकी कमजोरियों को भी उजागर किया।*

संवैधानिक संस्थाएं, प्रशासन और सरकारी एजेंसियां पहली बार भाजपा के प्रभाव में उसके लिए काम करती नजर आई। उन पर पार्टी की 'बी' टीम होने का कथित आरोप भी लगा। राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के गठजोड़, संसद में बहुमत की ताकत से न केवल संसद की प्रतिष्ठा को धूमिल हुई, बल्कि सब कुछ बौना लगने लगा। यहाँ तक कि संविधान भी छोटा लगने लगा। जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया वह संविधान में विश्वास रखने वालों को परेशान करने वाला था। जो लोग संविधान की शपथ लेकर संसद सदस्य बने, उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि अगर 400 पार सीटें आईं तो वे संविधान बदल देंगे। सत्ता में मौजूद पार्टी के इस अहंकार के कारण लोकसभा चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी और विपक्ष ने देश की जनता को संदेश दिया कि

संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। बल्कि संविधान का मतलब समानता का अधिकार है, जो देश की आजादी और उसकी स्वायत्तता से जुड़ा है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके अधिकार और संसाधनों का हिस्सा छीनकर कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण, गरीबों और कमजोरों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। जनता ने इसे समझा और सत्ता के नशे में चूर होकर आसमान में उड़ रही भाजपा को स्पष्ट जनादेश से वंचित रखा।

इसी वर्ष देश की संघीय व्यवस्था, लोकतंत्र और पारंपरिक संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किये जाने के उदाहरण भी सामने आये। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता का एक दुर्लभ उदाहरण भी इसी काल में देखने को मिला। केंद्र सरकार ने राज्यों के हिस्से का पैसा नहीं दिया। ममता बनर्जी से लेकर हेमंत सोरेन तक गैर-बीजेपी सरकारों ने इसकी शिकायत की। झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने जनता को बताया कि राज्य का केंद्र पर 126,000 करोड़ रुपये बकाया है। यह राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुनाव जीतने के लिए झारखंड में अपने चिरपरिचित नफरती एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। रोटी, बेटी, माटी, बांग्लादेशी, हिंदू मुस्लिम का सवाल उठाया लेकिन जीत हेमंत सोरिन की हुई। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल भी खुलकर खेला गया। नीतियां भी कॉरपोरेट्स का हित साधने के लिए बनाई गईं। वैसे तो सरकार का काम लोगों की भलाई के लिए नीतियां बनाना होता है, लेकिन इस दौर में सब कुछ उलट गया। राजनीतिक त्रासदी के इस दौर में यह भी देखने को मिला कि एक कॉरपोरेट मित्र कितना ताकतवर हो सकता है। इसके मुताबिक अगर आर्थिक नीतियां बनानी हों तो संसद भी कोई हैसियत नहीं रखती। संसद नहीं चल पा रही लेकिन सरकार अडानी के सवाल पर बात करने को तैयार नहीं है।

संसदीय बहुमत और कॉरपोरेट की ताकत के चलते सरकार ने जनहित की जगह निजी हित साधने वाली नीतियां बनाईं।

इसी साल देश की राजनीति की एक भयावह तस्वीर उभर कर सामने आई। जिसमें लोकतंत्र के मंदिर संसद की परिभाषा गायब दिखाई दी। देश का सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भाजपा के राजनीतिक ध्रुवीकरण के नारे के तहत ही गूंजता हुआ नजर आता है। देश की अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट पूंजी पर टिकी और राजनीति के चलती हुई दिखाई देती है। स्वतंत्रता के 78 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही देश को विकसित बनाने का नारा बुलंद हुआ। इसमें भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया गया। लेकिन ये कैसी स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी पांच किलो मुफ्त राशन पर निर्भर है। इस देश का बजट 6.5 करोड़ लोगों के टैक्स से मिलने वाले राजस्व के आधार पर पेश किया जाता है। इस देश में असमानता इतनी बढ़ गयी है कि भागीदारी का सवाल सपना बन गया है। इस काल में भारत के विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। उसका भारत की जड़ों से कोई लेना-देना नहीं है।

इस संकट में विपक्ष एक उम्मीद बनकर उभरा है। 2024 के चुनाव में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन वह लोगों तक संविधान का संदेश पहुंचाने में जरूर सफल रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष की एकता को तोड़ने की कोशिश करता रहा और अब भी कर रहा है। लेकिन विपक्ष बग़ैर डरे डटा हुआ है। ऐसी सत्ता मीडिया, संस्थाओं और न्यायपालिका के माध्यम से लंबे समय तक सुखद सपने नहीं दिखा सकती, जिसकी जड़ें जनता से कट चुकी हों। शायद ये 2024 का सबसे बड़ा संदेश है।

****

लेखक : पत्रकार एवं स्तंभकार तथा यू एन एन के संपादक है।

जनवरी 26: गणतंत्र दिवस पर विशेष

संवैधानिक शासन के 75 साल बाद कहां हैं हम

प्रो राम पुनियानी

भारत की संसद ने दो दिन तक देश के संविधान पर चर्चा की. विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमारे संविधान में समाज के कमज़ोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए अनेक प्रावधान हैं मगर उसके बावजूद ये वर्ग परेशानहाल हैं. मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है.

इसके विपरीत, सत्ताधारी भाजपा ने नेताओं ने संसद के अन्दर और संसद के बाहर भी कहा कि संवैधानिक मूल्यों पर हमले नेहरु (नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने के लिए संवैधानिक संशोधन) ने शुरू किये और यह सिलसिला इंदिरा गाँधी (आपातकाल) से होते हुए राजीव गाँधी (शाहबनो) और राहुल गाँधी (विधेयक को फाड़ना) तक चला. उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक बुराईयों की जड़ में नेहरु-गाँधी परिवार है और उसी ने संविधान को नुकसान पहुँचाया है.

भाजपा नेता और हिन्दू राष्ट्रवादी चिन्तक लम्बे समय से कहते आए हैं कि भारत का संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है, उसे औपनिवेशिक ताकतों ने हमारे समाज पर लादा है और वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से मेल नहीं खाता. उनका यह तर्क भी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टिकरण करने और उनका वोट बैंक बनाने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया.

जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान उन मूल्यों का प्रतिनिधि है जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान उपजे. संविधान तैयार करते समय हमारी सभ्यता की लम्बी परंपरा का ख्याल भी रखा गया. जिन लोगों ने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया और जो उसकी पीछे की विचारधारा में आस्था रखते थी, भारतीय सभ्यता की उनकी समझ, उन लोगों से बहुत भिन्न थी जो औपनिवेशिकता-विरोधी आन्दोलन से दूर बने रहे और ब्रिटिश शासकों के आगे नतमस्तक रहे. जहाँ आज़ादी का आन्दोलन भारत को समृद्ध विविधताओं वाला एक बहुवादी देश मानता था वहीं स्वाधीनता आन्दोलन से दूर रहने वाले उसे हिन्दू सभ्यता मानता था. ऐसे लोगों को बहुवाद पसंद नहीं है और वे मानते हैं कि बहुवाद को शिक्षित, आधुनिक नेताओं ने देश पर थोपा है.

> *जस्टिस शेखर कुमार यादव के सांप्रदायिक भाषण का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन पर सवाल बना हुआ है।*

संघ परिवार यह भूल जाता है कि भारतीय सभ्यता को हिन्दू सभ्यता बताना, हमारी सभ्यता में जैन, बौद्ध, ईसाई और सिक्ख धर्मों व इस्लाम के योगदान को नकारना है. हिन्दू राष्ट्रवादियों के सबसे प्रिय भगवान राम को देखने के भी अलग-अलग तरीके हैं. कबीर के लिए राम सर्वव्यापी निर्गुण हैं तो गाँधी के लिए राम सभी धर्मों के लोगों के रक्षक हैं. गाँधी कहते थे 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम'. जवाहरलाल नेहरु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "भारत: एक खोज" में लिखा है कि "भारत एक प्राचीन स्लेट है, जिस पर कई परतों में अलग-अलग कालों में विचार और भावनाएं दर्ज की गईं मगर कोई नयी परत, पिछली परतों को न तो पूरी तरह ढँक सकीं और न मिटा सकी." नेहरु बड़े गर्व से सम्राट अशोक के शासनकाल को याद करते हैं, जिन्होंने अपने कई शिलालेखों में वैदिक हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविकों के साथ एक-समान व्यवहार करने की बात कही है.

संघ परिवार और उसके चिंतक जहाँ भारत को विशुद्ध ब्राह्मणवादी हिन्दू देश मानते हैं वहीं गाँधी, नेहरु इत्यादि इसे सभी भारतीयों का देश मानते थे. भारत की संविधान सभा मोटे तौर पर उस धारा का प्रतिनिधित्व करती थी, जो राष्ट्रीय धारा थी, जो वह धारा थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था. इसके विपरीत, भारत को ब्राह्मणवादी हिन्दू राष्ट्र मानने वाला आरएसएस हाशिये की धारा थी. दोनों धाराओं का यह अंतर, भारत के संविधान का मसविदा तैयार होने के समय से ही परिलक्षित होने लगा था.

अम्बेडकर और नेहरु का यह स्पष्ट मत था कि देश की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न की जाए और उसे पूरी तरह से लागू किया जाए. मगर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान के समीक्षा के लिए वेंकटचलैया आयोग का गठन किया. उस समय राष्ट्रपति डॉ के.आर. नारायणन ने बहुत सामयिक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि, "संविधान के कारण हम नाकाम नहीं हुए हैं, बल्कि हमनें संविधान को नाकाम किया है." यह बात मोदी सरकार के कार्यकाल के सन्दर्भ में एकदम सही है. इस दौर में संविधान में कोई बदलाव नहीं किये गए मगर संघ परिवार के कई सदस्यों ने ऐसा करने की इच्छा और ज़रुरत बताई और उन्हें शीर्ष नेतृत्व द्वारा फटकारा नहीं गया. "अब की बार चार सौ पार" का नारा इसी इच्छा का प्रतीक था. भाजपा चाहती थी कि उसे लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें हासिल हों ताकि वह संविधान को बदल सके.

देश में नफरत फैलाने वाले भाषण देने और बातें कहने वालों की संख्या में तेजी से इज़ाफा हुआ है. इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हैं इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव, जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद् के एक कार्यक्रम में कहा कि "भारत बहुसंख्यकों की मर्जी के अनुसार चलेगा."

जस्टिस यादव मे "समान नागरिक संहिता: एक संवैधानिक आवश्यकता" विषय पर बोलते हुआ कहा, "केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों की भलाई और प्रसन्नता के लिए फायदेमंद हो."

इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादव के कथन का समर्थन किया. यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यादव के सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाले भाषण का संज्ञान लिया है. मगर आदित्यनाथ के यादव को समर्थन का कौन संज्ञान लेगा?

वर्तमान स्थितियों पर एक सटीक टिप्पणी में जस्टिस अस्पि चिनॉय ने कहा, "भाजपा केंद्र में सरकार में है और उसके पास संसद में पूर्ण बहुमत है. मगर उसे भारत और उसके संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कानूनी तौर पर बदलने की कोई ज़रुरत महसूस नहीं हो रही है. राज्य और उसके विविध तंत्र उसके नियंत्रण में है और वह कानूनी तौर पर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदले बिना, उसके धर्मनिरपेक्ष संविधान को कमज़ोर करने और हिंदुत्व पर आधारित राजकाज कायम करने में कामयाब रही है."

आरएसएस संविधान को पश्चिमी और असंस्कारी बताकर मनुस्मृति को आदर्श मानता है, जबकि डॉ. अंबेडकर और नेहरू ने संविधान को भारतीय सभ्यता और बहुलवाद का प्रतीक बताया।

भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के सांप्रदायिक चरित्र का खुलासा उस समय ही हो गया था जब संविधान का मसविदा जारी किया गया था. इसके कुछ दिन बाद, आरएसएस के गैर-आधिकारिक मुखपत्र आर्गेनाइजर ने 30 नवम्बर 1949 के अपने अंक में लिखा, "भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है....भारत के प्राचीन संवैधानिक कानूनों, नामकरणों और भाषा का इसमें नामोनिशां तक नहीं है." मतलब यह कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने 'मनुस्मृति' को नज़रअंदाज़ किया!

लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए, हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के पितामह वी.डी. सावरकर को उद्दत करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने कहा, "भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. हमारे हिन्दू राष्ट्र में वेदों के बाद मनुस्मृति सबसे पूजनीय ग्रन्थ है, जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, रीति-रिवाजों, विचारों और आचरण का आधार रही है. सावरकर का कहना था कि मनुमृति की हमारे देश का कानून है.

अगर हम संविधान की मसविदा समिति के मुखिया डॉ अम्बेडकर और आरएसएस के एक सरसंघचालक के. सुदर्शन की तुलना करें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और आरएसएस के मुखिया ने भारत के संविधान को पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित बताते हुए जहा था कि हमें मनुस्मृति पर आधारित भारत का संविधान बनाना है.

****

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

दिसंबर 6: पुण्यतिथि

डॉ. अंबेडकर की दलित सबलीकरण की विरासत और भाजपा

विद्या भूषण रावत

डॉ.बीआर अंबेडकर भारत के उत्पीड़ित समुदायों के मुक्तिदाता और मुक्तिदाता बने हुए हैं। हालांकि, उन्हें दो राजनीतिक दलों के बीच में बांधने की कोशिशें उनकी विरासत की सतही और स्वार्थी समझ को दर्शाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक था, जो दलितों के दावे और सशक्तिकरण से असहज लोगों की हताशा को दर्शाता है।

डॉ. अंबेडकर का दर्शन देवी-देवताओं की भक्ति के बजाय मानव कल्याण के इर्द-गिर्द घूमता था। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मानव दर्शन को मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए - एक सिद्धांत जो चार्वाक की शिक्षाओं में भी प्रतिध्वनित होता है। बाबा साहब का असली संघर्ष किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था (बीएसओ) के खिलाफ था। इस व्यवस्था का समर्थन या विरोध विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा किया गया।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारतीय समाज में सामंजस्य स्थापित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। डॉ. अंबेडकर और कांग्रेस पार्टी के विचार अलग-अलग थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने विशेष रूप से इस प्रक्रिया के महत्व को पहचाना। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनसंघ के नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस प्रयास का हिस्सा थे। अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद, इनमें से किसी भी नेता ने एक-दूसरे को राष्ट्र-विरोधी या कमतर नहीं कहा। उन्होंने संसद में जोरदार बहस की, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा संविधान बना जो भारत की एकता का स्तंभ बना हुआ है।

> *आरएसएस संविधान को पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित बताकर मनुस्मृति को आदर्श मानता है, जबकि अंबेडकर ने इसे भारतीय सभ्यता और बहुलतावाद के खिलाफ बताया।*

आज, ऐतिहासिक घटनाओं के चुनिंदा संदर्भों ने हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचाया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक व्यापक आधार वाले संगठन के रूप में कांग्रेस स्वाभाविक रूप से विविध नेताओं और विचारों का एक मंच बन गई। स्वतंत्रता के बाद, इन नेताओं ने अलग-अलग पार्टियाँ बनाईं और लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए।

डॉ. अंबेडकर और डॉ. मुखर्जी दोनों ही नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे। जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो मुखर्जी ने हिंदू महासभा से खुद को अलग कर लिया, लेकिन मंत्रिमंडल में बने रहे। उन्होंने 1951 में नेहरू-लियाकत समझौते के कारण इस्तीफा दिया, लेकिन किसी मजबूरी में नहीं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, नेहरू, अंबेडकर और मुखर्जी जैसे नेताओं ने परस्पर सम्मान साझा किया - जो एक अलग, अधिक सम्मानजनक राजनीतिक युग की पहचान थी।

डॉ. अंबेडकर को अपने करियर के दौरान काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर हिंदू कोड बिल को लेकर, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया एक प्रगतिशील कानून था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, केएम मुंशी, पुरुषोत्तम दास टंडन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे प्रमुख नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। यहां तक कि सरदार पटेल भी विपक्ष की ओर झुके थे।

केवल नेहरू और अंबेडकर ही इस सुधार की वकालत करने में एकजुट थे। डॉ. अंबेडकर को कौन बेहतर सम्मान देता है- कांग्रेस या भाजपा- इस पर बहस बेमानी है। उन्हें भारत रत्न भाजपा ने नहीं बल्कि वीपी सिंह ने दिया था, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों द्वारा बदनाम नेता थे। सिंह ने नव-बौद्धों को आरक्षण भी दिया, संसद में अंबेडकर की तस्वीर स्थापित की और अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। उन्होंने अंबेडकर के विचारों को संरक्षित करने और फैलाने के लिए अथक प्रयास किया, अक्सर दिवंगत रामविलास पासवान जैसे नेताओं के साथ मिलकर।

डॉ. अंबेडकर की भव्य स्मारक या प्रतिमाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी विरासत का सही सम्मान करने के लिए, राजनीतिक नेताओं को यह करना चाहिए:

* भूमि सुधार लागू करें और हाशिए पर पड़े लोगों को भूमि का पुनर्वितरण करें।
* सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करना।
* प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण रोकें।
* सभी क्षेत्रों में आरक्षण को पूर्णतः लागू किया जाए।

डॉ. अंबेडकर की विरासत संविधान के प्रारूपण में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के एक अथक आलोचक थे, जिन्होंने इसके ग्रंथों, देवताओं और प्रथाओं को चुनौती दी। 1956 में नागपुर की दीक्षाभूमि में उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में बुद्ध से प्रेरित मानवतावाद के मार्ग का आह्वान किया गया था।

अंबेडकर के दृष्टिकोण को कायम रखने के लिए हमें उन्हें संविधान के बारे में महज बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय हमें उनके आदर्शों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: संसाधनों का पुनर्वितरण, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और भारत की विविधता को

विपक्ष ने कमजोर वर्गों की स्थिति पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने नेहरू-गांधी परिवार को संवैधानिक मूल्यों के क्षरण का जिम्मेदार ठहराया।

प्रतिबिंबित करने वाला समावेशी शासन सुनिश्चित करना।

भारत के लिए डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण प्रगतिशील मानवतावाद का था, न कि प्रतिगामी धार्मिक रूढ़िवाद का। उनका भारत कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देगा, जिसका नेतृत्व ज्ञान में निहित होगा, विभाजन में नहीं। अब समय आ गया है कि राज्य दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और सभी पर पड़े समुदायों के लिए कल्याणकारी उपाय करे, चाहे उनका धर्म या जातीयता कुछ भी हो। तभी हम डॉ. अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं।

****

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं, जो दलित अधिकारों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर गहरी छानबीन करते हैं।

सुविचार

"सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही सबसे मजबूत रास्ता होता है।"

****

"जो कठिनाइयों का सामना करता है, वही जीवन में सफल होता है।"

****

"समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय वापस नहीं आता।"

****

"सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।"

****

"जिंदगी में जो खो गया, उसका शोक मत करो; जो है, उसे पूरी तरह से जीओ।"

****

कॉर्पोरेट कार्यशैली में पारदर्शिता और जनहित की आवश्यकता

प्रो शिवाजी सरकार

अडानी प्रकरण से पता चलता है कि कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। निर्णायक रूप से कार्रवाई करने में विफलता से भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिष्ठा और निवेशकों के विश्वास को और नुकसान पहुंचने का खतरा है। नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बनाए रखना और व्यावसायिक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद सदस्यों को भी आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे कॉरपोरेट निकायों को एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं (एमआरटीपी)-प्रकार के कानूनों को पुनर्जीवित करने सहित विधायी सुधारों पर जोर देना चाहिए। ऐसे उपायों से एकाधिकार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा उपायों को फिर से लागू किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सत्यम लेखा घोटाले जैसी घटनाएं दोबारा न हों।

अडानी प्रकरण ने कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की गंभीर कमी उजागर की है।

गौतम अडानी सिर्फ़ एक और भारतीय अरबपति नहीं हैं। पिछले एक दशक में, उनका समूह, अडानी समूह, भारत सरकार का एक विस्तार बन गया है। समूह की गतिविधियाँ बंदरगाहों, कारखानों और बिजली संयंत्रों तक फैली हुई हैं, जिनमें अक्सर सरकारी अनुबंध या लाइसेंस शामिल होते हैं। इस घनिष्ठ संबंध ने अडानी समूह को भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है, खासकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से।

हालांकि, हाल के आरोपों ने अडानी के उल्कापिंड के उदय पर छाया डाल दी है। 21 नवंबर को, अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोप लगाए। आरोपों में भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत की पेशकश करना और अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए धन जुटाने के दौरान वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को योजना के बारे में गुमराह करना शामिल है। ये आरोप, हालांकि अमेरिकी कानून के तहत आपराधिक अपराध हैं, लेकिन इनका भारत के व्यापार और निवेश संबंधों, खासकर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उभरते बाजारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

अडानी समूह द्वारा भारतीय कानून के तहत खुद को निर्दोष बताने के बावजूद, इसका नतीजा काफी

महत्वपूर्ण रहा है। समूह ने बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों का जोरदार खंडन किया है, अदालतों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसी नियामक एजेंसियों को हलफनामे प्रस्तुत किए हैं। फिर भी, निवेशकों का विश्वास डगमगा गया है। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच को अडानी से संबंधित संस्थाओं में अपने पति के विवादास्पद निवेश के कारण जांच का सामना करना पड़ा, जिससे समझौता किए गए नियामक ढांचे की धारणा को बल मिला।

बाजार की प्रतिक्रिया गंभीर रही है। अमेरिका में अभियोग की ताजा खबर के बाद, अदानी समूह की 11 कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में ₹38,000 करोड़ की गिरावट आई है। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने समूह की तीन संस्थाओं के लिए अपने दृष्टिकोण को घटाकर "नकारात्मक" कर दिया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय भागीदार अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केन्या ने अवास्तविक शर्तों का हवाला देते हुए अदानी समूह के साथ 2.6 बिलियन डॉलर का सौदा रद्द कर दिया - यह बांग्लादेश में इसी तरह के मुद्दों की याद दिलाता है। यहां तक कि श्रीलंका में अदानी के निवेश भी जांच के दायरे में हैं।

अडानी समूह पर लगे आरोपों के कारण निवेशकों का विश्वास और भारतीय कंपनियों की विश्वसनीयता कमजोर हुई है।

भारतीय कॉरपोरेट्स पर इसका व्यापक प्रभाव गहरा है। भारतीय कंपनियों की विश्वसनीयता दांव पर लगी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। यह स्थिति 2009 के सत्यम घोटाले के नतीजों को दर्शाती है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय ऑडिटिंग फर्म से जुड़े अकाउंटिंग धोखाधड़ी ने भारत की कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को बुरी तरह से धूमिल कर दिया था।

भारत की मौजूदा कॉर्पोरेट प्रशासन चुनौतियों की जड़ें 1990 के दशक में नीतिगत बदलावों में देखी जा सकती हैं। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एकाधिकारवादी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एमआरटीपी अधिनियम बनाया गया था, जिसे आर्थिक उदारीकरण के दौर में धीरे-धीरे कमजोर किया गया। 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विलय और अधिग्रहण पर प्रवेश-पूर्व प्रतिबंध हटा दिए, जिससे अधिक कॉर्पोरेट-अनुकूल वातावरण की स्थापना हुई। 2009 तक, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-I सरकार ने औपचारिक रूप से एमआरटीपी अधिनियम को समाप्त कर दिया, और इसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू कर दिया।

कॉर्पोरेट कुशासन को रोकने और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एमआरटीपी जैसे कानूनों की पुनर्स्थापना आवश्यक है।

हालांकि इन बदलावों का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में कॉर्पोरेट कुशासन के खिलाफ सुरक्षा उपायों को कमजोर कर दिया। मजबूत जांच और संतुलन की अनुपस्थिति ने कुछ कंपनियों को बहुत कम जवाबदेही के साथ काम करने की अनुमति दी है, जिससे अडानी प्रकरण जैसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं।

अडानी विवाद और सत्यम घोटाले के बीच समानताएं मजबूत विनियामक निगरानी की आवश्यकता को उजागर करती हैं। 2009 के सत्यम घोटाले में संस्थापक रामलिंग राजू द्वारा कंपनी के खातों में हेराफेरी की गई थी, जिसने कॉर्पोरेट प्रशासन में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। इसके बाद शुरू किए गए सुधारों के बावजूद,

हाई-प्रोफाइल घोटालों की पुनरावृत्ति से पता चलता है कि मौजूदा उपाय अपर्याप्त हैं।

एमआरटीपी-प्रकार के कानून को पुनर्जीवित करना इन मुद्दों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ऐसे कानून न केवल आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकेंगे बल्कि नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, संसद को निगमों को जवाबदेह ठहराने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जबकि पिछले संसद सत्रों में कॉर्पोरेट कदाचार पर जोरदार बहस हुई है, ऐसे मामलों पर वर्तमान चुप्पी चिंताजनक है। उदाहरण के लिए, हाल ही में केवल एक सांसद ने संसदीय समितियों को प्रभावित करने वाले कॉर्पोरेट उपहारों का मुद्दा उठाया।

भारत को आर्थिक विकास और नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

भारत को कॉर्पोरेट विकास को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में विश्वास को फिर से बनाने के लिए MRTP-प्रकार के सुरक्षा उपायों की वापसी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह के सुधार भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ेंगे, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए इसका आकर्षण बढ़ेगा। इसके अलावा, संसद को एक निगरानीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कॉर्पोरेट संस्थाएँ नैतिक मानकों से समझौता किए बिना आर्थिक विकास में योगदान दें।

अडानी प्रकरण में विश्वसनीयता में आई गिरावट कॉर्पोरेट प्रशासन की अनदेखी की कीमत की एक स्पष्ट याद दिलाती है। भारत के विधिनिर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे निर्णायक रूप से कार्य करें, कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा को दबाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय पारदर्शी तरीके से संचालित हों और देश के दीर्घकालिक विकास में योगदान दें। अगर देश वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो वह इन सबक को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक है।

सोशल मीडिया से

चरित्र का कमीनापन और मक्कारी
व्यवहार में चमचागीरी और दलाली
निश्चित करती है सफलता तुम्हारी.

****

जो कहीं नहीं पहुँचे
खड़े रह गये
पाँव, उनकी सोच की
बेड़ियों में जकड़े रह गये.

****

आसान तो कुछ भी नहीं होता
खाना पीना सो जाना ही केवल
आसान है होता जब तुम चाहते हो
कुछ बदलना कुछ बेहतर करना
ज़िंदगी में आसान नहीं होता! सतत
प्रयास आसान नहीं होता!

****

सुकूँ के पल ज़रूरी हैं
अपनी खुसूसियत के लिए खुद में भी
वही अहसास महसूस हो, ज़रूरी है
रूहानियत के लिए.

****

इश्क ने पहले ही खबर ले ली जालिम
रहबर के जुल्मो सितम तकसीम होने
तक

~ डा. रवीन्द्र कुमार

क्या अब अमेरिका और कनाडा में बसना एक दिवास्वप्न होगा

प्रभजोत सिंह

उत्तरी अमेरिका को अपना नया घर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए चीजें शायद वर्ष 2025 में उतनी अच्छी नहीं रही हैं। जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में वापस लौटेंगे। कनाडा भी एक नये प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में है।

कनाडा और अमेरिका दोनों ने दक्षिण एशिया से और विशेष रूप से भारत से वर्ष 2024 में रिकॉर्ड आव्रजन देखा, यह अब समाप्त होने वाला है और अपने पीछे मीठी और खट्टी यादें छोड़ रहा है। उन लोगों का भविष्य अनिश्चित है जिनके पास अमेरिका या कनाडा में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन सभी लोगों को निर्वासित करने के अपने इरादे को कोई स्पष्ट किया है जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

उनकी पहली कुल्हाड़ी उन लोगों पर पड़ेगी जिनकी या तो आपराधिक पृष्ठभूमि है या जो वर्तमान में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। पर विदेशियों की संख्या लाखों में हो सकती है और नए अमेरिकी प्रशासन को राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेशों का पालन करने में लंबा समय लग सकता है।

कनाडा भी पिछले वर्षों में अपनी लगातार बदलती और आप्रवासी समर्थक नीतियों के कारण पैदा हुई अव्यवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत है। स्थिति को हाथ से फिसलता हुआ देखकर जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार नई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके व्यवस्था बहाल करने के लिए बेताब है, अब पिछली नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कानूनी रूप से कनाडा में आए युवा उम्मीदवारों की भी परेशानी बढ़ रही है क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि "नए नियमों के कारण उनके लिए स्थायी निवास की स्थिति की गारंटी नहीं है।

> *2025 में अमेरिका और कनाडा में सत्ता परिवर्तन से अप्रवासियों की स्थिति कठिन हो सकती है।*

जब सरकारों ने बीच में ही अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव किया, तो हज़ारों उम्मीदों वाले लोगों ने, संबंधित अधिकारियों की नीतियों और कार्यक्रमों पर भरोसा करते हुए, यह महसूस किए बिना कि उनका "डूबना अपरिहार्य होगा" छलांग लगा दी। उनमें से कई लोग दिन-प्रतिदिन बयानों, नीतियों और योजनाओं की घोषणा के कारण कगार पर हैं। जब अमेरिका और कनाडा की अप्रवासियों द्वारा लाए जा रहे अरबों डॉलर के अलावा "सस्ते श्रम" या "मानव शक्ति" की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अप्रासियो का खुले दिल से स्वागत किया। अब, संकट से उबरने के बाद, विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद, उन्हें लगता है कि "अप्रवासी प्रवाह को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है।"

नए नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन जो लोग कनाडा और अमेरिका का बसने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। आप्रवासन एक बहुआयामी घटना है। इतना कि लोग जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए अंतरराष्ट्रीय और भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। कोई भी कानून दोष रहित नहीं होता। जो लोग विदेश में बसने की सोच रखते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके और साधन खोज लेते हैं। यदि हाल के दिनों में, "अवैध आव्रजन और ट्रैवल एजेंट" मानव तस्करी के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी अवैध साधनों का उपयोग कर रहे थे, तो अब उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली भी बदल दी है। उन्होंने उम्मीदवारों को विदेश भेजने के लिए वैध और अवैध दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने न केवल मौजूदा प्रणालियों का फायदा उठाया, जिसमें कनाडा द्वारा शुरू किए गए 10 साल के वीजा या एक्सप्रेस एंट्री शामिल हैं, बल्कि अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें उम्मीदवारों को तस्करी के लिए "राजनीतिक शरण मार्ग" का इस्तेमाल करना शामिल है, जिसके लिए उन्हें भारी मात्रा में फीस देनी पड़ती है।

इन एजेंटों का मानना है कि भोले-भाले उम्मीदवारों को उनके मूल देशों के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें लेने के लिए प्रेरित करना, उनके उम्मीदवारों के लिए "राजनीतिक शरण" के मामले को मजबूत करेगा। इससे राजनीतिक शरण चाहने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिन्हें बदले में उन देशों से विशेष उपचार मिलता है, जिन्हें वे अपना नया घर बनाना चाहते हैं। संयोग से, इन "राजनीतिक शरण चाहने वालों" की एक बड़ी संख्या अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय से थी, जो हमेशा अपने दावे को अपने मूल देश में लौटने की स्थिति में "सताए जाने" के डर पर आधारित करते थे।

उद्यमी जनशक्ति और आव्रजन एजेंट भी युवा सक्षम आव्रजन उम्मीदवारों को विदेश भेजने के लिए "वैध और अवैध दोनों साधनों" को मिलाने का एक और मॉडल लेकर आए हैं। हाल ही में भारत में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी कार्यप्रणाली का पता लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कनाडा की सीमा से अमेरिका में युवाओं की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में कुछ कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता की जांच की।

यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत के बाद की गई थी, जो कुछ वर्ष पहले कनाडा-अमेरिका सीमा को अवैध रूप से पार करने का प्रयास करते समय अत्यधिक ठंड के कारण मर गए थे।

इस रैकेट के पीछे के दिमाग कुछ कनाडाई कॉलेजों के साथ मिलकर काम करते थे, जो छात्रों को छात्र वीजा दिलवाकर दाखिला दिलाते थे। कनाडा में पहुंचने के बाद, वे कॉलेज से बाहर निकलकर पूरी फीस वापस मांगते और फिर अमेरिका की सीमा से अमेरिका के लिए निकल पड़ते, बिना यह जाने कि वहां ऐसा करना आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रम्प के नए शासन के तहत, वे निर्वासित होने वाली पहली सूची में होंगे क्योंकि उनके पास अमेरिका में प्रवेश करने और रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। कानूनी रास्ते भले ही बंद हो गए हों या सिकुड़ गए हों, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं। वे सभी उम्मीद में जी रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि साल 2025 उनके लिए किस्मत लेकर आएगा।

पहले 25 वर्षों के लिए, हमारी जनसंख्या हर बार घट गई, जब भी इसे मापा गया," उन्होंने कहा कि "कार्यक्रम ने जनसंख्या के आकार के मामले में हमारे लिए बदलाव प्रदान किया है।" उन्होंने सुझाव दिया कि संघीय सरकार को यह समझना चाहिए कि उत्तरी ओंटारियो के शहरों की जरूरतें दक्षिणी ओंटारियो के शहरों से अलग हैं। उन्होंने कहा, "दक्षिणी ओंटारियो में पैदा हुए सामर्थ्य संकट के लिए हमें भुगतान न करें, क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि जारी रखने में मदद कर सकते हैं और कनाडाई अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं।"

ट्रम्प के वापसी और कनाडा में नीति बदलाव से अप्रवासियों के लिए भविष्य असमंजसपूर्ण हो गया है।

उनके विचारों की पुष्टि थंडर बे के मेयर केन बोशकॉफ़ ने भी की, जिन्होंने आव्रजन पर संघीय सरकार के रुख़ के बारे में इसी तरह की चिंताएँ साझा कीं। उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुत जगह है और बहुत सारी नौकरियाँ हैं क्योंकि खनन उद्योग वास्तव में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।" उन्होंने कहा, "समुदाय खुद भी, शैक्षिक दृष्टिकोण से और एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में, बहुत अच्छा कर रहा है," उन्होंने दावा किया कि थंडर बे जल्द से जल्द अधिक आवास बनाने और अधिक आप्रवासियों को आकर्षित करने और उन्हें रहने के लिए लुभाने के लिए पर्याप्त मनोरंजक गतिविधियाँ प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

पॉल लेफेब्रे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, "हम (संघीय सरकार से) कार्यक्रम को जल्द से जल्द फिर से खोलने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी नौकरियाँ हैं जो भरी जानी बाकी हैं।" "हमारे पास आवास है और हम उन्हें समायोजित करने में सक्षम हैं और निश्चित रूप से हमारे समुदायों में उनका स्वागत करते हैं।"

कनाडा की राजनीति में हुए घटनाक्रमों से उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान घोषित आव्रजन नीतियों और योजनाओं में तेजी से हुए बदलावों के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

सरकार में संभावित बदलाव के साथ आव्रजन कानूनों में बदलाव की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की उम्मीदों को एक और झटका तब लगा जब विपक्ष के नेता पियरे पोलीवरे, जो नए साल में संघीय चुनावों के बाद नई कनाडाई सरकार का नेतृत्व करने के लिए पसंदीदा हैं, ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वे "उन सभी लोगों को निर्वासित करेंगे जो अब कनाडा में रहने का दावा नहीं कर सकते हैं"। दो प्रमुख कनाडाई राजनीतिक दलों ने एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय से मुंह मोड़ लिया है और अमेरिका के

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी लाखों विदेशियों को निर्वासित करने की धमकी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की परेशानी और बढ़ गई है।

कनाडा और अमेरिका सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई मूल के छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य रहे हैं। कनाडा को अपना नया घर बनाने की उनकी उम्मीदों को अस्थायी रूप से बढ़ावा तब मिला जब कुछ ओंटारियो शहरों के मेयर चाहते थे कि संघीय सरकार आव्रजन नीतियों में अपने हाल के बदलावों पर पुनर्विचार करे क्योंकि वे अपनी जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि के गंभीर संकट की चपेट में थे।

जबकि मौजूदा संघीय सरकार ने अगले कुछ वर्षों में अपने अप्रवासी लक्ष्यों को काफी कम करने की घोषणा की है, उत्तरी ओंटारियो के सबसे बड़े शहरों के महापौरों का कहना है कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आबादी को बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक अप्रवासियों की आवश्यकता है। सॉल्ट सेंट मैरी, थंडर बे और सुडबरी के महापौर ओटावा से अपने समुदायों में कुशल श्रमिकों को पुनर्स्थापित करने वाले पायलट कार्यक्रम को स्थायी बनाने के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप्रवास नीति के लिए एक-आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण उत्तरी क्षेत्रों को लाभ नहीं पहुंचाता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉल्ट सेंट मैरी के मेयर मैथ्यू शूमेकर ने कहा कि अब बंद हो चुके ग्रामीण और उत्तरी आव्रजन पायलट कार्यक्रम ने शहर के नियोक्ताओं को विमान मरम्मत, इंजीनियरिंग और विभिन्न ट्रेडों में अत्यधिक कुशल पदों को भरने की अनुमति दी। शूमेकर ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी सफलता रही है," उन्होंने कहा कि आर्थिक अप्रवासियों के बिना इस क्षेत्र से ऐसी नौकरियाँ गायब हो जाएँगी।

पांच वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी ओन्टेरियो के पांच शहरों सहित कनाडा भर के छोटे समुदायों में आप्रवासियों को आकर्षित करना था, और इसने हजारों नए लोगों को स्थायी निवास का मार्ग प्रदान किया। इस वर्ष के प्रारम्भ में, संघीय लिबरल सरकार ने एक स्थायी ग्रामीण आप्रवासन कार्यक्रम बनाने का वादा किया था, साथ ही ग्रामीण और फ्रेंचभाषी समुदायों को लक्ष्य करते हुए इस वर्ष शरद ऋतु में दो अन्य पायलट कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की थी।

लेकिन कुछ महीनों बाद, ओटावा ने कहा

> *कनाडा और अमेरिका में नए आव्रजन कानूनों ने छात्रों और कामकाजी आव्रजनियों की उम्मीदों को झटका दिया है।*

कि वह स्थायी निवासियों के लिए अपने आव्रजन लक्ष्य में कटौती करेगा तथा आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए देश में अस्थायी निवासियों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी लाएगा। सरकार ने 2025 और 2026 दोनों वर्षों में 500,000 नए स्थायी निवासियों को लाने का लक्ष्य रखा था। अगले वर्ष का लक्ष्य 395,000 नए स्थायी निवासियों का होगा, तथा 2026 में यह संख्या घटकर 380,000 तथा 2027 में 365,000 रह जाएगी।

इन बदलावों के साथ-साथ अन्य संशोधनों ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को असमंजस में डाल दिया है क्योंकि अब उन पर कठोर नियंत्रण लागू किया जा रहा है। उनमें से कई छात्रों से न केवल अपने छात्र वीज़ा, बल्कि अपनी शैक्षणिक साख, जिसमें उपस्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं, अपलोड करने के लिए कहा गया है।

शूमेकर का मानना है कि हाल ही में किए गए बदलाव बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए थे, लेकिन सॉल्ट सेंट मैरी जैसे छोटे शहरों के विकास के लिए आप्रवासन महत्वपूर्ण था "क्योंकि अन्यथा हमारी मृत्यु दर हमारे नए जन्मों से अधिक हो जाती है," जिससे जनसंख्या और नगरपालिका कर आधार कम हो जाता है। नीति परिवर्तन के बारे में उन्होंने कहा, "एक ही तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता है।"

ग्रामीण और उत्तरी आप्रवासन पायलट की बदौलत पिछले कुछ वर्षों में 1,000 से अधिक लोगों को शहर में पुनर्स्थापित किया गया है और उन आप्रवासियों ने स्थानीय आबादी को 25 वर्षों में पहली बार 2024 में लगभग 78,500 लोगों तक बढ़ने में मदद की है। उन्होंने कहा, "2024 से सुडबरी के मेयर ने आगे कहा कि स्थानीय खनन उद्योग इंजीनियरों, वेल्डरों और मैकेनिकों की तलाश में है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्र भी कुशल श्रमिकों की तलाश में हैं। जबकि महापौरों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और चाहते थे कि संघीय सरकार परिवर्तनों पर पुनः विचार करे, अल्पमत लिबरल सरकार और नई सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की घोषणाओं ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की दिन-प्रतिदिन की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है , खेल कूद पत्रकार्ता में उनकी विशेष रूचि है और उन्होंने साथ ओलिंपिक कवर किये है। खेल - कूद के साथ ही वे व्यापर, वित्ति , स्वास्थ्य , विमानन और सिख-पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते है।

सामाजिक-मानवीय आधार पर शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता

डॉ. अनिल कुमार रॉय

शिक्षा का स्वरूप और पढ़ाये जाने वाले विषय सदा से सामाजिक, आर्थिक और कार्यालयी (राजकीय) आवश्यकताओं के पूर्त्यर्थ गढ़े भी जाते रहे हैं और उसका विस्तार भी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से होता रहा है। प्राचीन काल में धर्मशास्त्र, व्याकरण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि सीमित विषयों की शिक्षा तद् युगीन सीमित सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप थी। चूँकि

प्राचीन काल में शिक्षा मुख्य रूप से धर्म, शास्त्र, व्याकरण, और अस्त्र-शस्त्र संचालन जैसे सीमित विषयों तक सीमित थी, जो समाज की सीमित सामाजिक-आर्थिक और राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे। शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग कम थी, जिससे शिक्षा संस्थानों की संख्या भी बहुत कम थी और वे अधिकतर अनौपचारिक होते थे।

आर्थिक और राजकीय गतिविधियाँ सीमित थीं, इस कारण शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग भी कम थी। शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग कम थी, इसलिए शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएँ भी कम थीं। जो थीं भी, वे अनौपचारिक थीं।

वर्ष 1760 में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने न केवल राजतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था के बदले लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए राह बनायी, जिसके कारण वर्ष 1788 तक आते-आते अमेरिका में संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई, बल्कि सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों और कार्यालयी आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ। अब गाँवों में बिखरकर बसने वाली आबादी कल-कारख़ानों के निकट बसने लगी, जिससे सघन आबादी वाले नये नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में रहने वाले लोगों का रहन-सहन और आवश्यकताएँ पहले की अपेक्षा बदल गयीं। आर्थिक गतिविधि का मुख्य आधार भी कृषि उत्पाद से औद्योगिक उत्पादों की ओर जाने लगा। इसी समय से कारख़ानों, बैंकों, रेलों, प्रशासनिक कार्यालयों आदि में शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग भी बढ़ने लगी। अब इन आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा के पढ़ने-पढ़ाये जाने वाले विषयों और स्वरूप में भी युगांतरकारी परिवर्तन हुआ।

1760 में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बदलाव की दिशा तय की। अब आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार कृषि उत्पाद से औद्योगिक उत्पादों की ओर बढ़ गया। इस बदलाव के कारण शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग बढ़ी, और शिक्षा के विषयों और स्वरूप में भी बदलाव आया।

अब वेदों, धर्मग्रंथों, व्याकरण की जगह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य आदि वे विषय पढ़ाए जाने लगे, जो कारख़ानों, उद्योगों और राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और राजकीय व्यवहारों में उपयोगी होने के कारण इन विषयों के जानकारों की माँग बढ़ी और ये, प्राचीन विषयों की अपेक्षा, उन्नत रोज़गार के साधन भी बने। इसलिए

नये विषयों के पठन-पाठन के प्रति रुझान में वृद्धि हुई।

वृहद् पैमाने पर कल-कारख़ाने और कार्यालयों के खोले जाने के कारण वृहद् पैमाने पर शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी हुई। इसलिए अनौपचारिक शैक्षिक संस्थानों की जगह औपचारिक स्कूल-कॉलेज खोले जाने लगे ताकि इन कार्यों में नियोजन के लिए

नई शिक्षा प्रणाली में बदलाव औद्योगिक क्रांति के बाद

इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वाणिज्य जैसे विषयों की शिक्षा दी जाने लगी, जो औद्योगिक और राजकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी थे। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा में नये विषयों की ओर रुझान बढ़ा और वे विषय रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने लगे।

कार्य के अनुरूप प्रशिक्षित योग्यताधारी पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो सकें। इसी समय, नियुक्ति के लिए, विशाल पैमाने पर उपस्थित होने वाले अनजान उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता की पहचान के लिए परीक्षा बोर्ड भी विकसित किए गए।

चूँकि आर्थिक गतिविधि और राजकीय व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए उस आर्थिक और राजकीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप युवक-युवतियों को तैयार करने के लिए सरकार ने शिक्षा को भी अपने नियंत्रण में लेकर उसे एक औपचारिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। समाज के हाथों से खिसककर शिक्षा राज्य के नियंत्रण में चली गयी। अब राज्य आर्थिक-राजकीय आवश्यकताओं को पूर्त करने वाले विद्यालयों-विश्वविद्यालयों और विषयों को मान्यता देने लगा, पाठ्यक्रम निर्धारित करने लगा और यहाँ तक कि कार्यालयी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उसने विद्यालयों-महाविद्यालयों में अनुशासन का भी पाठ्यक्रम बना दिया। इस तरह पूरी शैक्षिक व्यवस्था सत्ता और पूँजीपतियों और उनके गठजोड़ के हितों की कठपुतली होकर रह गई। औद्योगिक विकास की कोख से उत्पन्न आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था की इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया में मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना से उसका संबंध-विच्छेद लगातार बढ़ता चला गया।

मानव-जीवन और मानवीय संवेदना तथा सामाजिक जीवन और सामाजिक चेतना से शिक्षा को विलग करने के लंबे प्रयास में सफलता के बाद सत्ता और पूँजीपतियों ने इसे अपने-अपने हितों में उपयोग करना शुरू कर दिया। एक तो यह हुआ कि आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था के प्रथम चरण में मानविकी आदि के विषय, जो मानवीय-सामाजिक दृष्टि से उच्चतर दर्जे के समझे जाते थे,

कविता

आपस मे लड़ती नहीं, पूजा और नमाज़

सरयू की पीर आई गोमती के तीर पड़ी
भक्त पर भीर अब मुक्ति बीज बोना है
राजनीति में है नीति , नीति में राजनीति
दृढ़ हुई धर्म नीति, वक्त नही खोना है.

नाहक हुए अधीर, बात बात में नज़ीर,
बहती है गंगा , हाथ बहुतों को धोना है.
लक्ष्मणपुरी में तभी मिलाप हुआ,
फैसला भी गोमती के तीर होना है.

कृष्ण हुए थे जेल में, फिर बंदी के राम,
भाग्य बड़ा भगवान से,हुए विधाता राम.
मुल्ला और महंत ही, झगड़े की आवाज़,
आपस मे लड़ती नहीं, पूजा और नमाज़.

~अनूप श्रीवास्तव

औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के विषय न रहने के कारण, दोयम दर्जे के विषय के रूप में पहचाने जाने लगे। दूसरी ओर राजनीतिक सत्ता ने इसे अपनी विचारधारा के प्रचार का साधन बनाना शुरू किया। उधर नवउदारवाद के खुले दरवाज़े से आकर पूँजीपतियों ने शिक्षा पर क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया को इस क़ब्ज़े के लिए आमंत्रित करते हुए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पथ प्रशस्त कर दिया गया। सत्ता और पूँजी के हितों को नीतिगत आधार देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लायी गई। शिक्षा पर राजकीय व्यय को कम करने, उसे राजनीतिक एजेंडा का हथियार बनाने

औद्योगिक क्रांति के बाद शिक्षा के स्वरूप में बदलाव के कारण औपचारिक शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकता महसूस की गई। अनौपचारिक शिक्षा की जगह स्कूल और कॉलेजों का विकास हुआ, ताकि उद्योगों और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो सके। साथ ही, परीक्षा बोर्डों की स्थापना की गई ताकि योग्यताओं की पहचान की जा सके।

और उसे पूँजीपतियों के हाथ में सौंप देने का ही नीतिगत दस्तावेज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।

इस तरह शिक्षा की धारा सत्ता और पूँजीपतियों के हितों की खेती को सींचने की ओर मोड़ दी गई है। सत्ता और पूँजीपतियों के हित सामाजिक और मानवीय मूल्यों से अलग हैं, कहें तो लगभग विपरीत। शिक्षा की इस नवीन धारा के रास्ते में सामाजिक आवश्यकताएँ और मानवीय संवेदना नहीं आती हैं। ऐसा ही रहा तो सामाजिकता बंजर ज़मीन की तरह हो जाएगी और मनुष्य रोबोट की तरह, पालतू और नियंत्रित। ऐसा होने में बहुत ज़्यादा समय बाक़ी नहीं है।

इसीलिए सामाजिक-मानवीय आधार पर शिक्षा के स्वरूप के पुनर्गठन की ज़रूरत है। इस नवीन परिस्थिति में शिक्षा के एक ऐसे प्रारूप की ज़रूरत है, जो राजनीतिक आवश्यकताओं की चेरी न बनकर सामाजिक हितों की पूर्ति करती हो, जो मनुष्य को क्लर्क-मात्र न बनाकर मानवीय गरिमा से भी संपन्न बनाये, जो शिक्षार्थी को औद्योगिक और व्यावसायिक समूहों के उपयोग का रोबोट-मात्र न बनाकर मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना से भी समन्वित कर सके, जो केवल धन्नासेठों के महलों की ही शोभा-मात्र न हो, बल्कि झोपड़ियों में भी अवसर की ज्योति जगाती हो, जो ख़ुद भी समानता पर आधारित होकर सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए मानसिकता और परिवेश का निर्माण करती हो, जो बेरोज़गारी के विरुद्ध रोज़गार के रास्ते बनाती हो, जो समावेशी हो और प्रेम और करुणा से पूर्ण जगत का निर्माण करती हो।

शिक्षा का नियंत्रण अब राज्य के हाथों में चला गया और उसे औपचारिक व्यवस्था में बदला गया। सरकार ने शिक्षा की दिशा को आर्थिक और राजकीय आवश्यकताओं के अनुसार तय किया, जिससे सामाजिक-मानवीय मूल्यों की भूमिका कमजोर पड़ने लगी।

सत्ता अपने लिए काम कर रही है, पूँजीपति अपने हितों की पूर्ति में संलग्न हैं। समाज, सामाजिक हितों, मानव और मानवीय हितों से उनका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में सामाजिक और मानवीय हितों के लिए समाज और सामाजिक लोगों को ही खड़ा होना होगा, उन्हें ही आगे बढ़कर शिक्षा के स्वरूप के पुनर्गठन की चिंता करनी होगी। यही आज की ज़रूरत है।

**सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्षरत हैं। उनके लेखन में हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्ष और एक न्यायसंगत समाज की आकांक्षा की गहरी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

****

डॉ. अनिल कुमार राव सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्षरत हैं। उनके लेखन में हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्ष और एक न्यायसंगत समाज की आकांक्षा की गहरी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की प्रताड़ना भुगतते छात्र

डॉ. नीरज कुमार

बिहार में पेपर लीक एक सामान्य प्रचलन हो गया है। वह भी उस दौर में, जब बिहार में नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से सुशासन के नाम पर राज कर रहे हैं। सवाल उठता है कि लगातार पेपर लीक होने के बावजूद इतने बड़े स्तर पर बहाली कैसे हो जाती है? सरकार आखिर इस लीक को रोक पाने में सफल क्यों नहीं हो रही है? बिहार के युवाओं को हर एक लीक के बाद आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन, बिहार के नेताओं का साथ क्यों नहीं मिल पाता? पेपर लीक का मामला मेनस्ट्रीम मीडिया में प्राइम डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं होता? हर पेपर लीक के बाद सरकार के नौकरशाह इसकी लीपापोती में क्यों जुट जाते हैं? आखिर पेपर लीक से किसके हितों को साधा जा रहा है? क्या परीक्षा माफिया इतने मजबूत हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं कि उनके खिलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती? अगर हाँ, तो इन माफियाओं का एक मजबूत गठजोड़ है सरकार एवं सरकारी तंत्रों के साथ।

उपरोक्त सन्दर्भ में अगर देखा जाय तो बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने में विफल हुई है। चाहे वो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा हो, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा हो या तत्काल में बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं प्रिलिम्स की परीक्षा हो। इतने बड़े स्तर के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली कैसे संभव है? यह एक सोचनीय विषय है। वह भी तब, जब राज्य की एजेंसी के माध्यम से इन भर्ती परीक्षाओं को लिया जाता है, जिसके पास न केवल इन परीक्षाओं को संचालित कराने का करने अनुभव है, बल्कि उसके पास पर्याप्त संसाधन के साथ -2 निर्णय लेने की क्षमता एवं उसके क्रियान्वयन के लिए पूरी मशीनरी उपलब्ध है। मोटे तौर पर देखा जाए तो बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद जी के शब्दों में " अगर कहीं जॉइन्ट होगा तो लीक की सम्भावना बनी रहेगी "। यानी उनका मानना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी को उतरदायी होना पड़ेगा। बिना उतरदायित्व के लीक को रोकना संभव नहीं।

बिहार में पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के शासन में इतनी बड़ी धांधली कैसे हो रही है।

इतनी बड़ी धांधली को सीधे शब्दों में समझना थोड़ा मुश्किल है। सामान्यतया देखा जाए तो किसी भी एग्जाम के तीन पार्ट होते हैं – पहला संरचनात्मक, दूसरा प्रक्रियात्मक एवं तीसरा जो कि दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो है फंक्शनल। इस कसौटी पर देखने की कोशिश करते हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं प्रिलिम्स को देखा जाय तो समझ में आ जाएगा कि कैसे तीनों स्तर पर सरकार से चूक हुई है। जैसे कि संरचनात्मक तरीक़े पर गौर किया जाय तो इसके तहत आयोग एवं उसकी पूरी मशीनरी को देखना होगा। सवाल उठता है कि जब आयोग की संरचना में ही खामी है तो कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे संभव है? कहने का तात्पर्य है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो वह भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कैसे ले सकता है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई हैं। इन महोदय पर निगरानी विभाग ने खुद एफआईआर दर्ज कर रखा है कि इन्होंने बिहार सरकार के महादलित

विकास निगम में साढ़े चार करोड़ का घपला कर रखा है। दूसरी बात कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनकी कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। यह अपने प्रेस-ब्रीफिंग में बोलते हैं कि इस बार की परीक्षा में प्रश्न पत्र स्तरीय होगा, जबकि प्रश्नपत्र छिछोला क़िस्म का निकला। यहाँ तक कि एक कोचिंग सेंटर के प्रैक्टिस सेट से ही ज्यादातर प्रश्न थे।

प्रक्रियात्मक स्तर पर देखें। इसके तहत प्रश्नों के स्वरुप या पैटर्न, प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग, सेंटर का निर्धारण एवं सीटिंग अरेंजमेंट आता है। आज तक हमने यह नहीं देखा था कि आयोग अपनी निर्णय-प्रक्रिया में कोचिंग संचालकों से सलाह मशविरा करता है। आयोग को अगर बदलाव करना होता है तो वह एक्सपर्ट कमिटी का गठन करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर।बदलाव कर देता है. यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी का अर्थ है, वैसे एक्सपर्ट जो पिछले

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रिलिम्स परीक्षा में धांधली ने सरकार की परीक्षा प्रणाली की नाकामी को उजागर किया है।

कई वर्षों से इस तरीक़े की परीक्षा में विशेषज्ञ हों। साधारणतया इसमें वैसे प्रोफेसर होते हैं, जिन्हें दस वर्षों का अनुभव होता है। वहीं इस बार परीक्षा से पहले ही आयोग ने कुछ चुने हुए कोचिंग संचालकों से पैटर्न में बदलाव के लिए सलाह मशविरा कर लिया। अब जबकि कोचिंग संचालक परीक्षा पैटर्न तय करने लगेंगे तो निष्पक्ष परीक्षा कैसे संभव है? रही बात सेंटर निर्धारण की तो आयोग को इस बात के लिए सूक्ष्म स्तर तक जाँच-परख करके निर्धरण करना होता है। महज सेंटर का रिकॉर्ड कैसा है, सेंटर किस प्रकार के वीक्षक को रखेगा, सेंटर सुप्रीटेंडेंट एवं सेंटर ऑब्जर्वर का कैसा सम्बन्ध है, इत्यादि। मीडिया रिपोर्ट में यह चल रहा है बापू सभागार में पहले से किसी खास कोचिंग संचालक की पकड़ थी। फिर उसे सेंटर बनाने के बाद वहाँ पर निष्पक्ष सेंटर सुप्रीटेंडेंट एवं सेंटर ऑब्जर्वर को क्यों नहीं तैनात किया गया? आयोग का प्रश्न कभी किसी एक सेट से नहीं मिल सकता है। क्योंकि प्रश्नों को तैयार करने के लिए भी यह विशेषज्ञों से मदद लेता है। जैसे, यदि राजनीति विज्ञान से प्रश्न पूछना है तो यह उस विषय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर से आग्रह करता है कि आप हमको पाँच सौ ऐसे प्रश्न बना कर दें। अब उस प्रोफेसर को भी पता नहीं होता है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है। साथ-ही-साथ आयोग उस प्रोफेसर पर ख़ुफ़िया निगरानी भी बनाए रखता है। अंततः आयोग कोचिंग के प्रैक्टिस सेट को भी सरसरी निगाह से देख लेता है कि उसने बाजार में कैसे प्रश्न दे रखे हैं। इतने सारे उपायों के बावजूद हू-ब-हू प्रश्नों के मिल जाने को महज़ संयोग नहीं कहा जा सकता है।

रही बात फंक्शन की तो इसके स्तर पर यह देखा जाता है कि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की समस्या या अफवाह की स्थिति नहीं बने। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। मसलन छात्रों को सेंटर तक पहुँचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। छात्रों को सही समय पर प्रश्नपत्र एवं ओएमआर शीट मिल जाए। इस स्तर पर भी सोशल मीडिया में पेपर लीक की खबरें, देर से प्रश्नपत्र मिलना, प्रश्नपत्रों की कमी आदि कई ऐसे पहलू हैं, जो आयोग के कार्यात्मक विकार (फंक्शनल डिसऑर्डर) को उजागर करते हैं।

परीक्षा माफियाओं का बढ़ता दबदबा और सरकारी तंत्र की नाकामी ने बिहार की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

वर्तमान परीक्षा में जो भी खामी हुई है, वह तीनों स्तर पर हुई है। अतः सरकार को चाहिए कि वो छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए पुनः परीक्षा का निर्णय ले।

****

लेखक वर्तमान में आईसीफाई लॉ स्कूल, आईसीफाई विश्वविद्यालय, देहरादून में विजिटिंग सहायक प्राध्यापक हैं, जहां वे विधिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

साहसी निर्णय लेने वाला एक सौम्य व्यक्ति

प्रो प्रदीप माथुर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में उनके बारे में काफी कुछ लिखा और कहा गया।

उन पर एक कार्यक्रम में एंकर ने मुझसे पूछा कि डॉ. मनमोहन सिंह की पहले और उनके बाद दो विपक्षी दल के प्रधान मंत्री रहे? दोनों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। आप उनकी तुलना किससे करना चाहेंगे अटल बिहारी वाजपेई से या नरेंद्र मोदी से?

मैंने कहा कि दोनों में से किसी के पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं रही है जितनी मनमोहन सिंह में थी। अगर बुद्धिमत्ता और गंभीर चिंतन की बात करें तो उनकी तुलना नरसिम्हा राव से कर सकते हैं। अगर हम उनके चरित्र, सादगी और ईमानदारी की बात करें तो उनकी तुलना लाल बहादुर शास्त्री से की जानी चाहिए।

डॉ. मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं जो उनकी मानवतावादी मनोवृति और उनके आर्थिक मामलों की समझ को दर्शाते हैं। केंद्र में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार थी। डॉ. मनमोहन सिंह दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार में शामिल होने आए थे। हम कुछ पत्रकारों ने उनसे अलग ले जाकर बात की। हमने उनसे पूछा कि उनके

इस विश्वास का आधार क्या है कि भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन सकता है।

डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां बैंकिंग प्रणाली की बदौलत अगर आप एक लाख रुपये से कोई कारोबार शुरू करते हैं तो सात साल में आप करोड़पति बन सकते हैं।

यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। हमने पूछा, यह कैसे संभव है?

डॉ. मनमोहन सिंह ने एक शिक्षक की तरह समझाया। यदि आप 1 लाख रुपये से कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और एक साल में कुछ मुनाफा कमाना शुरू करते हैं, तो एक साल के बाद आपको अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए किसी भी बैंक से 10 लाख रुपये का ऋण आसानी से मिल सकता है। अगर आप सही तरीके से निवेश कर सफलता हासिल कर लेते हैं और आप ऋण का भुगतान सही समय पर कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही एक करोड़ का लोन मिल जाएगा। आप चार-पांच साल में रकम चुका सकते हैं और फिर बड़ा लोन लेकर बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। सात साल में मेहनत, लगन और ईमानदारी से आप एक लाख से शुरू करके 10 करोड़ रुपये के उद्योग के मालिक हो सकते हैं। इस तरह का अवसर किसी और देश में मिलना संभव नहीं है। हमने वास्तव में डॉ.

साहब के दृष्टिकोण और भारत के भविष्य के बारे में उनकी सोच को

उन्होंने अपनी गहरी समझ और सोच से भारत की अर्थव्यवस्था को नया दिशा दी, जिसे आज भी सराहा जाता है।

सराहा।

दूसरी बात डॉ. मनमोहन सिंह के किसी समय रहे ड्राइवर ने बताई मुझको। मैं टैक्सी में दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रहा था। कुछ दोस्तों के फोन आ रहे थे और मैं चाय के लिए रास्ते में रुका। ड्राइवर ने पूछा, "सर क्या आप अखबारवाले हैं?" मैंने कहा हां पर तुम क्यों पूछ रहे हो? ड्राइवर ने कहा, सर, किसी समय में मनमोहन सिंह सर का ड्राइवर था। योजना भवन उनसे मिलने के लिए बहुत सारे पत्रकार आते थे। आप भी उन्हीं की तरह हैं।

मैंने पूछा, डॉ. मनमोहन कैसे आदमी हैं?

ड्राइवर ने कहा, "आप क्या कहते हैं सर, मैंने कई लोगों के लिए काम किया है लेकिन अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जैसे वह हैं।" काम के लिए वह अक्सर देर रात को ऑफिस से जाते थे। एक बार मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। मैं सुबह सर को लाने उनके घर नहीं जा पाया और हमारे कार्यालय का एक साथी ड्राइवर उन्हें घर से कार्यालय लाया था। शाम को कार्यालय के समय के बाद डॉ. मनमोहन सिंह सर अपने कमरे में बुलवाया और कहा तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम घर जाओ मैं बस से चला जाऊंगा।

मैं सन्न रह गया। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं। आप बस से घर जाएंगे? उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? यहां से नीचे उतरकर ऑल इंडिया रेडियो के सामनेवाले स्टैंड से बस मिलेगी और शाहजहां रोड उतर जाएंगे। उसके पीछे पंडारा रोड पर मेरा घर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, रात में बस में भीड़ भी नहीं होगी।

यह संभव नहीं था कि मैं चला जाऊं। मेरी नौकरी चली जाती अगर मैंने ऐसा किया होता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आदमी न होकर भगवान हो, जिन्हें हमारे जैसे छोटे आदमी का भी इतना ख्याल था।

चाय पीकर हम आगे बढ़े। लेकिन वह ड्राइवर और उसकी बात मुझे अब भी याद है। काश आज के हमारे राजनीतिक जीवन में इस तरह के लोग होते।

कुछ नेताओं को उनके कार्यकाल में सराहा जाता है, लेकिन जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो उनकी आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता है। वहीं, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जिन्हें सत्ता में रहते हुए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उनकी सराहना होती है। डॉ. मनमोहन सिंह ऐसे ही नेता थे। उनके जीवन और कार्यों का इतिहास भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा, बल्कि कई ऐतिहासिक सुधारों को लागू किया, जिनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं।

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया। यह कठिन समय था, लेकिन उन्होंने जीवन के इस कठिन दौर को सहन किया और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को कभी कम नहीं होने दिया। उनका परिवार सरल और मेहनती था, और मनमोहन सिंह ने भी अपनी पढ़ाई में अव्वल बनने के लिए बहुत मेहनत की। मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (UK) से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल. (Doctor of Philosophy) की डिग्री भी हासिल की। उनके शैक्षिक सफर के दौरान, उन्होंने उन समय के कुछ

अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया।

प्रमुख अर्थशास्त्रियों से शिक्षा ली, जो

बाद में उनकी नीतियों पर प्रभाव डालने वाले थे।

1991 में, जब भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि डॉ. सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाला। 1991 में भारत विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था, और इसके परिणामस्वरूप डॉ. सिंह को भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन (devaluation) के कठिन कदम को उठाना पड़ा।

डॉ. सिंह ने आयात-निर्यात नीति को लचीला बनाया, लाइसेंस राज को समाप्त किया और निजी क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता दी। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन सुधारों का उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़कर इसे मजबूती प्रदान की जाए। उन्होंने सरकारी कंपनियों में विनिवेश (disinvestment) और निजीकरण के कदम उठाए, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान आई। हालांकि, इन सुधारों के दौरान उन्हें कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को लेकर, लेकिन बाद में इन कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।

डॉ. सिंह का मानना था कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए और बैंकों को अधिक स्थिर बनाने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही, उन्होंने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई। उनके इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक मजबूत स्थान दिलाया।

2004 में, डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनका प्रधानमंत्री बनने का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि उनकी छवि एक गंभीर और तकनीकी अर्थशास्त्री की थी, जो राजनीति से दूर रहते थे। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और कई अहम योजनाओं की शुरुआत की।

> *उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और निष्कलंक चरित्र था, जो उन्हें राजनीति में आदर्श बनाता है।*

उनकी सरकार के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया, जिनमें "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" (MGNREGA), "खाद्य सुरक्षा कानून", और "शिक्षा के अधिकार कानून" शामिल हैं। इन योजनाओं ने भारत के गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीदें बनाई। MGNREGA के तहत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

इसके अलावा, उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकीं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से देश के नागरिकों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था।

डॉ. सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके आलोचकों का कहना था कि वे एक कमजोर प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी के प्रभाव में रहते थे। इसके अलावा, 2008 में भारत में आए आर्थिक संकट के बाद उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना पड़ा। उनके खिलाफ दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन और कोयला खनन में अनियमितताओं के आरोप लगे। इसके अलावा, हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले में भी उनका नाम लिया गया। हालांकि, डॉ. सिंह ने कभी भी इन आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उन्होंने हमेशा कहा कि "इतिहास मेरे बारे में वह निर्णय करेगा,

जो समकालीन मीडिया और विपक्षी दलों के विचार से परे होगा।" उनकी सरकार ने मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। उनकी बैंकिंग नीति और मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत को कम से कम नुकसान हुआ और वह वैश्विक मंदी के प्रभाव से बच सका।

डॉ. सिंह की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और ईमानदारी थी। उन्होंने कभी भी अपने पद का गलत उपयोग नहीं किया और न ही अपने परिवार या व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग किया। उनकी ईमानदारी और निष्कलंक चरित्र ने उन्हें पूरे देश में सम्मान दिलाया। वे हमेशा अपनी नीतियों और फैसलों के बारे में खुले तौर पर बात करते थे, और आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेते थे। उनकी सरकार के दौरान, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर योजना और नीति जनहित में हो और किसी भी तरह के निजी हितों से परे हो।

उनकी विनम्रता ने उन्हें राजनीति के विभाजन से ऊपर उठने की क्षमता दी। उन्होंने हमेशा सभी पक्षों के साथ संवाद की कोशिश की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सामूहिक हित में काम करने का प्रयास किया। उनका नेतृत्व इस बात का उदाहरण था कि कैसे एक नेता अपनी ईमानदारी, दृष्टिकोण और समर्पण से राजनीति में अंतर ला सकता है।

डॉ. मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारत की अर्थव्यवस्था काफी संकटग्रस्त थी, लेकिन उन्होंने उसे स्थिर किया और उसे वैश्विक आर्थिक मंच पर एक मजबूत स्थान दिलाया।

> *उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की एक नई राह बनाई, जिससे व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया।*

उनकी सरकार ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। खासकर मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने के लिए उन्होंने सच्चर समिति की स्थापना की, जो भारतीय मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट लेकर आई। इस रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा में कमी को उजागर किया और इसके लिए सरकारी नीतियों में सुधार की आवश्यकता बताई।

डॉ. सिंह के नेतृत्व में, भारत ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उनके नेतृत्व की विशेषता धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उनके कार्यकाल में, भारतीय समाज में कई बदलाव हुए, जिनका सकारात्मक प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की, जिसमें हर नागरिक को समान अवसर मिलें और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन और कार्य भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अमूल्य धरोहर बन चुके हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल वैश्विक मानकों के अनुरूप ढाला, बल्कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लागू किया। उनका व्यक्तित्व एक नेता की तुलना में अधिक एक इंसान के रूप में उभरा, जो न केवल ईमानदार था, बल्कि अपने देश के प्रति समर्पित भी था।

आज, जब हम भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो इसके पीछे डॉ. सिंह की दूरदर्शिता और उनकी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका नेतृत्व, उनकी ईमानदारी और उनके द्वारा किए गए सुधार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया गुरु और मीडिया मैप के संपादक है।

बुलंदी की पराकाष्ठा

श्री दिनेश नारायण वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' में प्रकाशित हुई जो 27 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद "मेरे समय की मेरी कहानियाँ" के रूप में हुआ। प्रस्तुत कहानी उसी संग्रह से ली गयी है। - संपादक

यह एक महज़ इत्तफाक था कि मेरी मुलाकात उन महान सज्जन से हुई जिनके व्यक्तित्वयका प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर सालों गुज़र जाने के बाद आज भी मौजूद है। हुआ यूँ कि में उन्हें अपने सहयोगी के साथ शाम को दिखाई जाने वाली फिल्म शहीद के लिए विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शामिल होने के लिए आमंत्रित करने गया था। 'शहीद' जाने माने निर्माता एवं कलाकार मनोज कुमार द्वारा निर्मित प्रसिद्ध फिल्म थी। फिल्म का प्रदर्शन देहरादून जनपद के एक ब्लाक ऑफिस के प्रांगण में रात का अंधेरा होने पर होना था।

वह उस ब्लाक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। वह डॉक्टर कम तपस्वी अधिक लगते थे। लम्बा इकेहरा ज़िस्म, गोरा रंग, घुँघराले बाल जो गर्दन तक लटके हुए थे और काली सफेद लम्बी दाढ़ी, सब मिलाकर उन का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। उन्हें लोग डॉक्टर बाबू के नाम से बुलाते थे।

उन्होंने हमारा बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चाय पीते हुए मैंने उन्हें मुख्य अतिथि का न्योता दिया और यह अपेक्षा थी कि वह इसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे क्योंकि डॉक्टर बाबू ने वह फिल्म देखी भी नहीं थी। यह वह ज़माना था जब दूरदर्शन घरों तक नहीं पहुँचा था और उस जैसे स्थान पर फीचर फिल्म का प्रदर्शन एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोग दूर-दराज के गांवों और कस्बो से फिल्म देखने आते थे। क्योंकि हम उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे इसलिए हम लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि हमारे निमंत्रण को वह स्वीकार कर लें। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने हमारी प्रार्थना को बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। हमने उन्हें मनाने की हर तरह से कोशिश की लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हमें बाद में अहसास हुआ कि वह अपने स्थान पर ठीक ही थे।

अपने शब्दों का ठीक से चयन करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इस फिल्म के बारे में जानता हूँ जो भारत माँ के ऐसे सुपुत्र की कहानी है जिसकी देश की आज़ादी के लिए दी हुई कुर्बानी अपना अलग ही स्थान रखती है। लेकिन मेरे लिए किसी और को भगत सिंह के रूप में देख पाना संभव ही नहीं है क्योंकि मैं चंद उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें उन को वास्तव में बहुत करीब से देखने का मौका मिला।" उनकी आँखे चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे वह अतीत के अंधरे में खोए हुए हों और समझ न पा रहें हों कि आगे क्या कहें।

मैं उस पतले दुबले व्यक्ति के सौम्य चेहरे के पीछे उस शहीद की झलक ढूँढ़ने लगा जिसके साथ उन्होंने कुछ समय अवश्य ही व्यतीत किया होगा। हालाँकि उन्होंने यह बात कही नहीं किन्तु फिर भी उनसे बात करते हुए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह कभी शहीद भगत सिंह की टीम का हिस्सा रहे होंगे और उन्होंने उस व्यक्ति को चलते फिरते बातचीत करते मीटिंग्स करते हुए देखा होगा जिसकी विधुतगति जैसी फुर्ती मशहूर है।

थोड़ी ही देर में उन्होंने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में शहीद भगत सिंह के बारे में बताना शुरू किया "आसमान पर तेज़ चलते हुए बादलों के समान पहाड़ी इलाकों में मीलों दूर दूर तक वह चले जाया करते थे और दूसरे दिन सुबह को बिना थके ऐसे आ जाते थे मानों बस कुछ ही दूर गए थे। वह एक अति सुंदर युवक थे जिसके चेहरे से नजर उठा पाना मुश्किल हुआ करता था।"

जब डॉक्टर शहीद भगत सिंह से जुड़ी बातें सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ कांप रही थी और आँखों में आंसू भरे हुए थे। हम तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और हमारा यही मन करता रहा कि वह बोलते रहें और हम बस सुनते रहें। लेकिन आखिर में उन्होंने जो कहा उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचा।

उन्होंने कहा, "भगत सिंह केवल एक ही थे। न दूसरा हुआ न उनकी तरह कोई दूसरा होगा। मेरी भी इच्छा थी उनकी तरह बनू लेकिन मैं गलत था, यह कहते हुए उनका गला ग्लानि से भर उठा। "जो मुश्किल वह रोज़ आसानी से झेल लिया करते थे मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जो शारीरिक कष्ट उनको मिले वह उनकी विराट आत्मा ही बर्दाश्त कर सकती थी। वही थे जो एक वैरागी का जीवन व्यतीत करते हुए भयानक से भयानक कार्यों को अंजाम दे देते थे। मैं एक भीरु व्यक्ति के समान भाग के आ गया

और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन काटने लगा। वह जिस मिट्टी के बने हुए थे मैं उसका सौवां हिस्सा भी नहीं था। वह अमर हैं और मैं यहाँ एक छोटे से गाँव में एक आम व्यक्ति की तरह गुमनाम जीवन बिता रहा हूँ, सहमा सहमा, मौत से डरा हुआ, जबकि उन्होंने मौत को ऐसे आलिंगन किया था जैसे वह उन की अर्धांगिनी हो। मैं किसी रूप से भी उन की नकल को स्क्रीन पर देख ही नहीं सकता।" मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रख दिया हो।

जब मैं लौट के आया तो मैं काफी मायूस था। किन्तु एक बात से खुश भी था। डॉक्टर साहब खुद भले ही ना आए हों लेकिन उन्होंने मेरे अंदर बहादुर माताओं के बहादुर और महान सपूतों के बारे में एक नए तरीके से सोचने का तरीका सुझाया। लौटते वक़्त मेरे दिमाग को एक ही बात कुरेद रही थी कि ऐसे ही और बहुत से बहादुर लोग शहीद भगत सिंह क्यों नहीं बन सके। बहादुर महान सपूतों की छवि मेरे मस्तिष्क पर छाई हुई थी।

शारीरिक रूप से शक्तिशाली ऐसा ही एक व्यक्तित्व भवानी का था जो मेरी आँखों के सामने उभरने लगा। मैंने उनकी शारीरिक शक्ति के बहुत से किस्से सुने हुए थे और मुझे लगता था कि वह शायद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देश भक्तों के समान शारीरिक पीड़ा और कष्टों को झेल सकते थे किन्तु फिर भी भवानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्यों न बन सके। शायद इसलिए कि यह लोग अनोखे थे लेकिन फिर भी बहुत साधारण, बल्कि साधारण से भी बदतर थे।

भारी जिस्म, चौड़े कंधे और शरीर गठा हुआ था और इसलिए भवानी शारीरिक रूप से काफी प्रभावशाली थे। चेहरा गोल और रंग गेहुआ और उस पर घनी मूँछे उनके चेहरे को काफी रोबदार बनाती थी। सर टकला था लेकिन सफेद घने बालों की एक रेखा एक कान से लेकर दूसरे कान तक ऐसे फैली हुई थी कि उनका टकला सर भी बड़ा भला काता था। भवानी एक खुले तांगे में चला करते थे और वह इतना तेज़ घोड़ तांगा दौड़ाते बगक चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस कांस्टेबल घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर घबरा कर थे कि हो जाया करता था। पुलिस वाले को भवानी के घोड़े के टापों की आवाज़ ऐसे ही याद रहती थी जैसे उन्हें अपनी वर्दी और पेटी का रंग।

उन्हें भगवान ने न सिर्फ एक स्वस्थ प्रभावशाली शरीर दिया था बल्कि बेइन्तहा शारीरिक शक्ति और हिम्मत भी। वह चाकू और लाठी बखूबी चलाने के लिए मशहूर थे। आार के हिंसात्मक रवइयों के कारण लोग उन्हें बहादुर शैतान के नाम से जानते थे और यही कारण था लोग उनसे डरते भी बहुत थे और नफरत भी करते थे। लेकिन जहाँ दुश्मनों के लिए वह एक आतंकवादी शैतान थे और पुलिस के लिए सरदर्द, वहीं गरीब और कॅमज़ोर व्यक्तियों के लिए मसीहा थे और महिलाओं के रक्षक। अधिकतर उनसे जुड़ी हुई कहानियां गैंग वॉर की हैं जो इसलिए हुआ करती थी कि कोई दूसरा उनसे किसी भी चीज़ में जीत न सके, चाहें दौड़ हो या फिर कुश्ती। लड़ाई की तो बात ही अलग थी।

सुना जाता था, कि जब वह विद्यार्थी थे तो इस कदर शैतानी करते थे कि उनके मास्टर उनके दोनों हाथों को अपनी कुर्सी के नीचे दबा कर पूरी कक्षा को पढ़ाया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि न तो उन्होंने कभी माफी मांगी न हथियार डाले। जब वे शक्तिशाली युवक हो गए तो एक बार एक गाँव के बदमाशों ने उन्हें लाठियों से ऐसे मारा कि वह ऊपर से नीचे तक ज़ख्मी हो गए। वह अकेले पड़ गए थे और गाँव के युवक बदमाशों ने लाठी से लगातार उन पर प्रहार किए। जब उनका केस अदालत में गया तो गाँव के बदमाशों में से किसी एक ने यह आरोप अपने सर ले लिया कि उसने भवानी को मारा था लिहाज़ा वही सज़ा का हकदार था बाकी सब निर्दोष थे। भवानी यह सुनकर अपने पूरे ज़ख्मी शरीर के साथ अदालत में उठकर खड़े हो गए और प्रतिपक्ष को ललकारते हुए बोले, "अदालत उन्हें मौत की सज़ा सुना दे यदि इनके दस उपस्थित लोग उन्हें छू कर भी दिखा दें।" न्यायाधीश ने जो शायद भवानी के किस्से सुनाते रहे थे मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे मालूम है। आधा शहर भी मिलकर उनको नहीं मार सकता" और बीस के बीस आरोपियों को दोषी मानते हुए सज़ा सुना दी थी।

लेकिन अब मुझे यह सोचकर ताज्जुब नहीं होता कि बेइन्ताह बहादुरी के बावजूद भवानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्यों नहीं बन सके। वह इसलिए कि उनके पास शारीरिक शक्ति और हिम्मत तो उतनी थी जितनी शायद भगत सिंह में रही होगी लेकिन उन में भगत सिंह की आत्मा दूर तक नहीं थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भवानी जैसे लोग जिन्हें वरदान में बेइन्तहा शारीरिक बल और हिम्मत मिली हुई थी बजाए गैंग वॉर के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे होते। इसके विपरीत, मुझे फिर यह सोच के दुःख हुआ कि डाक्टर बाबू के पास भगत सिंह जैसे महान देश भक्त की आत्मा तो अवश्य रही होगी किन्तु जो साहस और शारीरिक बल उनके समान होना चाहिए था वे उन में दूर दूर तक नहीं था। असल में भगत सिंह जैसे लोग तब ही पैदा होते है जब उनमें इन दोनों प्रकार के गुणों का समन्वय होता है। लेकिन ऐसा होता सदियों में कभी कभी ही है।*************

हास्य व्यंग

नया साल शुभ हो : नए साल में हम नये छप्पर फाड़े

अनूप श्रीवास्तव

लो आ गया नया साल। इस बार ती बार जी दुनिया मुट्ठी में कई साल करने की चिल्ल पों मचाएं हुए हैं। पिछले साल हमने कोशिश की तो मुट्ठी में दुनिया नहीं आई

पर सैकड़ों मुट्ठी धोटाले और घपले आ गये। अब घोटाले और हमारी संस्कृति के अनिवार्य अंग बन गये हैं। इनके बिना हमारी संस्कृति उसी तरह अधूरी है जैसे आतंकवाद के के बिना पाकिस्तान बदनियती के बिना चीन । इसलिए अब हमें घपलों और घोटालों की खर-दूषण राहु कैतु, सूर्पणखा, पूतना आदि की तरह सुपरहिट जोड़ी मानकर इन्हें स्वीकार कर लेना चहिए, कैसे भी,जिस देश में जितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा यह उतना ही संपन्न होगा। चर्चित होगा.अब अरबों-खरबों के घाटाले नेपाल या न्यूजीलैंड में तो ही नहीं सकते। इन देशों की माली हालत भी इतनी नहीं होगी जितनी हम घोटालों में फूंक देते हैं। दुनिया में जितने देश हैं उनसे चार गुना ज्यादा हमारे यहां जांच कमेटियां है.इस साल औरों को चिल्लाने का मौका दें। दूसरों को भी छप्पर फाड़ने का अवसर है।

इस बार हम सब मिलकर दुनिया भले मुट्ठी में न करें पर अपनी मुट्ठी जरूर मजबूत रखें.अपनी एनर्जी का संरक्षण करें। उसे बर्बाद न होने दें। हम संसद को न चलने देने में अपनी एनर्जी इतनी बेस्ट कर देते हैं कि अपने घोटालों को भी ठीक से ढक नहीं पाते। बिना छके ही जांच कमेटियों के हवाले कर देते हैं। हम दिल्ली में चिल्ला चिल्लाकर खुद को निढाल कर देते हैं फिर एनर्जी रहित पांच साल पड़े पड़े बिता देते हैं। यह तक नहीं सोचते कि जब हमें मौका था, हमने किया अब दूसरों की भी कुछ करने का मौका दें। अब जब मौका हाथ से फिसल गया तब हाय हाय करने से क्या हाथ आने वाला है.

अब नया साल आया है तो सब कुछ नया नया हीना ही चाहिए। जरूरी है कि हम पुराने साल के घपलों -घोटालों पर धूल डालें और अपनी जमीन को कुछ नया करने के लिए खुद को झाड़-पोंछकर खड़ा करें। फिर आगे भला भला होने कि उम्मीद के पैंतरे चलायें.

यह सबको पता है कि हमारी सभी योजनाएं दस प्रतिशत लोगों की ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। शेष नब्बे प्रतिशत को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं, लेकिन यह जो आम आदमी है, बिल्कुल आम की तरह होता है, चाहे डाल पर पका ले या पाल में रखकर।

इसे सिर्फ चुनाव के समय खास माना जाता है। फिर उसे चूसकर गुठली की तरह फेंक दिया जाता है। जैसे बीते साल कितने ही घपलै घौटाले हमने बिना झाड़े फूंके,फेंक दिए। सिर्फ उन्हें ही घपला माल जिस पर हमारा ठप्पा नहीं लगा था। जो हमारे पाले में नहीं आया उसे बख्शने का क्या मतलब। अभी हम शोर मचा रहे हैं आपका

> *आ गया नया साल, लेकिन इस बार क्या होगा अलग? साल दर साल हम घोटालों से घिरे रहे हैं, और हमारी संस्कृति में यह अनिवार्य अंग बन गए हैं। घोटालों के बिना हमारी पहचान अधूरी है, ठीक वैसे जैसे आतंकवाद के बिना पाकिस्तान की बदनियत। इस साल, चाहे दुनिया मुट्ठी में न हो, हमारी मुट्ठी कम से कम मजबूत होनी चाहिए। हम अपने गुस्से और उर्जा को ऐसे मामलों में खर्च करते हैं कि खुद अपने मुद्दों पर ही ध्यान नहीं दे पाते। अब नया साल है, तो इस साल को बिना पुराने घपले-घोटाले खोले एक नई दिशा में लेकर चलें!*

मौका आयेगा तब आप शोर मचा लेना।

वैसे भी राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी हमेशा किल्लत में रही है। हाईकमान के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी.अब कुछ भी बोलने की आजादी है। कहीं भी बोलने की आजादी है समर्थन देने की आजादी है। समर्थन आपस लेने आजादी है। मंहगाई बढ़ाने और बहुत ज्यादा बढ़ाने की आजादी है। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद को इन्जवाय करने आजादी है और कहीं भी कुछ भी न करने, न होने देने की आजादी है।

तो क्या यह संभव है कि हम सब मिलकर कसम खायें कि सन् दी हजार पचीस में कोई आदर्श या अनादर्श घोटाला नहीं करेंगे। एक ही साल की तो बात है। पलक झपकते बीत जाएगा ये एक साल। दो हजार उनतिस जैसे ही आ जाए कसम दे देना और यदि देश, जनता, विकास जैसी चीजें कुछ मायने रखती हों तो इसको हनुमान की पूँछ की साल दर साल बढ़ाते जाएं।

नया साल आपको शुभ हो. आपको ही नहीं सभी को शुभ हो. वैसे

बेगर्स हैव नो च्वाइस! नया साल हमें तोहफ़े मे नहीं बख्शीश मे मिला है. जो तोहफ़े हमें मुग़ल शासक नहीं दे सके, वो हमें गौरांग प्रभु बख्शीश मे दे गये. हम स्वतंत्राता /गणतंत्र दिवस मनाकर अपनी नई पीढ़ी को जताते हैं -कभी हम भी गुलाम थे. ठीक उसी तरह नया साल मनाकर दी गयी इस बख्शीश को भी याद कर लेते हैं. इस तरह नया साल हमारे तीज त्योहारों पर भी भारी पड़ जाता है.

आइये! नए साल में हम नया छप्पर फाड़े.

नये साल में यह कहना मुश्किल है किवह हमें किसे घाट उतारेगा. हो सकता है जो घाट घाट का पानी पिये हुए है वें न घर के रहे न घाट के और जो घाट पर खडे हैं रहे है नए साल में छलाँगे लगाते नजर आये। हर नया साल बधाई के साथ धमकी देता नज़र आता है. नए साल का क्या है.?किसी को पदस्थ करेगा तो किसी को अपदस्थ करेगा. वैसे जनता बेचारी हमेशा अपदस्थ रहती है.आगे भी कोई बदलाव हो इसको उम्मीद नजर नहीं आती।

जिस प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर मे लांच हो जाती है,ठीक उसी प्रकार पुराना साल आउटडेटेड होकर "नया साल" धारण कर लेता है। पुराने साल कि रवानगी और नए साल कि आमद आधी रात को दर्ज करने की परमपरा हम पूरी अंग्रेजीयत के साथ मनाते हैं और अपने फागुन को याद तक नहीं करते.

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

क्षणिकाऐ

राजनैतिक और भूख

हम फैलातें हैं, भूखमरी।

मरते हैं भूख से बच्चे, बूढ़े और जवान

और फिर रोटी के टुकड़े फेंककर खींचते हैं फोटो

और फिर हमें भूख से बचाते हैं

बच्चे, बूढ़े और जवान

इंसान का अहंकार

इंसान का अहंकार शरीर के मरने के साथ खत्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर का साथ निभाता है,

अगले जन्म में साँस लेने के साथ फिर चालू हो जाता है और वह मूर्ख यह भी नहीं जानता उसके सब कष्टों और बार बार जन्मों का कारण यही अहंकार है।

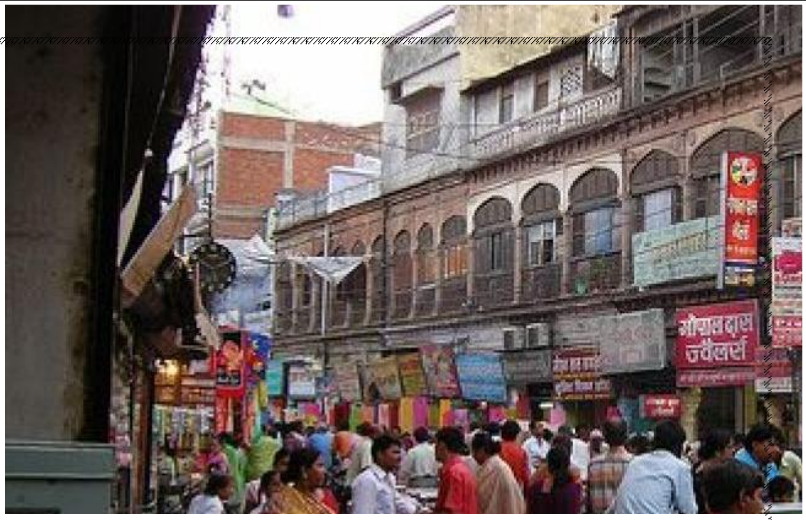

हरि ॐ
SHARMA JI KI CHAI
The Taste of Quality
34,T.n. Road,lalbagh,Lucknow
DAKIA

अंदाज़-ए-लखनऊ

वक़्त का तकाज़ा है गंगा जमनी तहज़ीब

डॉ. सतीश मिश्रा

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अपनी खास गंगा-जमुनी तहज़ीब और विविध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर हर किसी के लिए कुछ खास रखता है—उर्दू शायरी के प्रेमियों से लेकर टुंडे कबाब, कुल्फी और चाट के शौकीनों तक। यहां की गंगा-जमुनी तहज़ीब ऐसी संस्कृति है जो धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र के भेदभाव को नकारती है।

लखनऊ की संस्कृति ने हमेशा बाहरी लोगों का स्वागत किया है। यह शहर हर किसी को समान स्थान और सम्मान देता है। राजनीति, शिक्षा, कला या खेल—हर क्षेत्र में लखनऊ ने अपनी खास पहचान बनाई है। इसकी तहज़ीब में इंसानियत और उदारता का मेल है, जो इसे सबसे अलग बनाता है।

लखनऊ की इस तहज़ीब का सबसे बड़ा उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी। वह न केवल एक महान नेता थे, बल्कि लखनऊ के लोगों के दिलों में खास जगह रखते थे। टुंडे कबाब और लखनवी व्यंजनों का उनका प्यार और लखनऊ के मुसलमानों के साथ उनका मधुर संबंध इस तहज़ीब की मिसाल है।

लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब ने हमेशा नफरत और सांप्रदायिकता को पीछे छोड़ा है। यहां हिंदू-मुस्लिम दंगों की कहानियां नहीं, बल्कि शिया और सुन्नी विवाद भी हिंदुओं की मध्यस्थता से सुलझाए गए हैं। यह शहर हर धर्म और समुदाय के लोगों को समानता और भाईचारे के साथ जोड़ता है।

लखनऊ का चिकनकारी शिल्प, जो कुर्तों और साड़ियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है। मुख्य रूप से मुस्लिम कारीगर इसे तैयार करते हैं और हिंदू व्यापारी इसे बाजार तक पहुंचाते हैं। यहां के शाही व्यंजन—शामी कबाब, टुंडे कबाब, मटन कोरमा, मलाई की गिलौरी और लखनवी पान—हर किसी के दिल और ज़ुबान पर छा जाते हैं। चौक की चाट और शिवधर की ठंडाई जैसे स्थानीय व्यंजन भी लखनऊ की खास पहचान हैं।

आज के समय में, जब भारत सांप्रदायिक संघर्ष और अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के माहौल से गुजर रहा है, लखनऊ की तहज़ीब एक रामबाण की तरह है। यह संस्कृति सिखाती है कि कैसे हर किसी को गले लगाया जाए और दोस्त-दुश्मन सबको समान सम्मान दिया जाए।

लखनऊ की उदार परंपरा भारत के अस्तित्व के लिए एक समाधान हो सकती है। यह शहर धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकता का प्रतीक है। इसकी तहज़ीब और नफासत हमें सिखाती है कि नफरत को कैसे पीछे छोड़कर इंसानियत को प्राथमिकता दी जाए।

लखनऊ न केवल एक शहर है, बल्कि यह साझा संस्कृति और भाईचारे का एक उदाहरण है। इसकी अनोखी तहज़ीब हमें सिखाती है कि विविधता में ही एकता है। यही "अंदाज़-ए-लखनऊ" है, जो इसे न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में खास बनाता है।

वह शायर जिसे भूल पाना नामुमकिन है

मोहम्मद अहसान

दिसंबर में उर्दू शायरी के महान शायर मजाज़ की पुण्यतिथि होती है, जिनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिन्दा है। 1955 में मात्र 40 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएँ उन्हें एक किंवदंती बना चुकी हैं। मजाज़ की शायरी में प्रेम, विफलता और निराशा जैसी गहरी भावनाएँ समाहित हैं, और उनकी कविताएँ न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का चित्रण करती हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालती हैं।

मजाज़ की प्रसिद्ध नज़्म "आवारा" ने उन्हें खास पहचान दिलाई, जबकि "रात और रेल" जैसी रचनाएँ उनकी संवेदनशीलता को उजागर करती हैं। उनकी शायरी में नारीवाद का भी अनूठा दृष्टिकोण था, जहां वे महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से बाहर देखने का समर्थन करते थे।

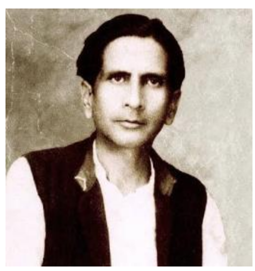

समाज में बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते

हुए, उन्होंने "बोल री धरती बोल" जैसी नज़्में लिखी। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी शायरी ने उन्हें अमर बना दिया। उनके विचारों की सरलता और शब्दों की सुंदरता उन्हें उर्दू साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है।

****

अड्डेबाजी जो लखनऊ की खास पहचान है

प्रदीप कपूर

लखनऊ में बीते 75 वर्षों में अड्डेबाजी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो राजनीति, साहित्य, कला, संस्कृति और छात्र आंदोलनों का केंद्र बन चुकी है। हजरतगंज का काफी हाउस 1940 से आज तक चर्चा का मुख्य केंद्र रहा है, जहां राजनेता, साहित्यकार, कलाकार, और छात्र नेता नियमित रूप से मिलते थे। यह जगह लखनऊ की सांझी विरासत और राजनीति का प्रतीक बन गई।

यहां पर राम आडवाणी, तजीन हबीबुल्लाह, और कई प्रसिद्ध शायर जैसे अली सरदार जाफरी, मजाज, और कैफ़ी आज़मी भी आते थे। हिंदी साहित्य के महान लेखक यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा भी यहां बैठकर चर्चाएँ करते थे।

काफी हाउस में आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और चंद्रशेखर जैसे प्रमुख नेता भी शामिल होते थे। वीर बहादुर सिंह और लालजी टंडन ने यहां अपनी राजनीतिक शुरुआत की। टंडन ने इसे एक राजनैतिक पाठशाला माना, जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग बहस करते थे।

काफी हाउस ने लखनऊ की तहजीब को बनाए रखा और यह विचारों के आदान-प्रदान का केंद्र बना। कोरोना काल से पहले यहां नियमित चर्चाएँ होती थीं, और आज भी यह लखनऊ की सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर का हिस्सा है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

तबले के जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन

उस्ताद जाकिर हुसैन, तबले के जादूगर, भारतीय संगीत की दुनिया के एक अद्वितीय नाम हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रक्खा, तबले के महान उस्ताद थे, जिन्होंने बचपन में ही उन्हें संगीत की शिक्षा दी।

जाकिर हुसैन की तबला वादन की शैली में खासियत थी कि उनकी थाप से घोड़े की चाल, रेल की छुक-छुक और हवाओं की आवाज़ तक सुनाई देती थी। उन्होंने संगीत के साथ-साथ फिल्म साज और हीट एंड डस्ट में अभिनय भी किया।

11 साल की उम्र में पहला संगीत कार्यक्रम देने वाले जाकिर ने 12 साल की उम्र में अमेरिका में प्रदर्शन किया और अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आमंत्रण पर ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लिया।

जाकिर हुसैन का लखनऊ से गहरा नाता था। 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका जीवन और कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जाकिर हुसैन ने तबले को एक संवाद का माध्यम बना दिया, और उनका योगदान हमेशा याद रहेगा।

****

लेखिका : जागरण आईनेक्स्ट, अमर उजाला में पत्रकार और एनबीटी में विशेष संवाददाता; 2020 से फ्रीलांस पत्रकार।

महामहिम का अभिनन्दन भांग के गोले से

अनूप श्रीवास्तव

अमृतलाल नागर जी का अभिनन्दन जौनपुर में एक यादगार घटना थी। जौनपुर के कवि रूप नारायण त्रिपाठी ने तय किया कि नागर जी का भव्य स्वागत राज्यपाल के हाथों किया जाए।

लेकिन इस आयोजन की तैयारी में कई हास्यपूर्ण घटनाएं घटीं। ठाकुर प्रसाद सिंह, जो सूचना विभाग के उपनिदेशक थे, शुरू में इस विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन अंततः वे भी तैयार हो गए।

नागर जी के स्वागत के लिए जौनपुर में तोरण द्वार लगाए गए थे, लेकिन हकीकत में राज्यपाल किसी अन्य समारोह में व्यस्त थे।

जब नागर जी हिंदी भवन पहुंचे, तो वहां की तैयारी बहुत मामूली थी।

हालांकि, रूप नारायण त्रिपाठी ने अपने काव्यात्मक संचालन से माहौल को जीवंत बना दिया। नागर जी ने अभिनन्दन समारोह के दौरान अपने चांदी के गिलौरीदान से भांग का गोला निकाला और जल चढ़ा दिया, मानो वे स्वयं राज्यपाल का अभिनन्दन कर रहे हों।

बाद में राज्यपाल खुद समारोह में पहुंचे और नागर जी को तलवार और चांदी की छड़ी भेंट की।

इस समारोह में राज्यपाल ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना नागर जी का सम्मान किया।

यह घटना उनकी जीवनशैली, हंसी-मजाक और साहित्यिक योगदान का प्रतीक बन गई।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

अंग्रेजी राज के विरोध का प्रतीक रिफा-ए-आम क्लब

अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लखनऊ का यह वाक्या बहुत मशहूर है। लखनऊ के एक नामी तालुकेदार अंग्रेजों के क्लब, जो उस वक्त छत्तर मंजिल में था वहां गए थे। अपने रवायती अंदाज, शेरवानी और टोपी पहने हुए तालुकेदार साहब को क्लब के गेट पर ही रोक लिया गया। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया । तालुकेदार साहब को क्लब के बाहर से ही लौटा दिया गया और यह बात उन्हें तीर की तरह चुभ गई। वह फौरन सर मोहम्मद अली मोहम्मद महाराजा ऑफ महमूदाबाद के पास पहुंचे और अपना दुख बताया। उस वक्त उनके साथ दूसरे तालुकेदार, नवाब और कई राजा भी थे। सबने इस तकलीफ को महसूस किया और फिर उसी बैठक में आम लोगों के लिए एक क्लब को शुरू करने की इबारत को लिखा गया। इस क्लब को शक्ल देने के लिए वजीरगंज स्थित एक खूबसूरत इमारत को चुना गया जिसका निर्माण नवाबों ने ही करवाया था। यूरोपियन पैटर्न पर बनी इस बिल्डिंग का आर्कीटेक्ट बेमिसाल था। यहां के डोम से लेकर अंदर बने तहखाने नायाब कारीगरी का नमूना थे। क्योंकि जानकारों का यह मानना है कि बिल्डिंग पहले से बनी थी और इसके भवन के आर्किटेक्ट, खूबसरती को देखते हुए ही इसे क्लब बनाने के

लिए चुना गया था।

बस फिर क्या था एक कमेटी बनी और क्लब को अमली जामा पहनाने के लिए सभी ने फंड दिया। अंग्रेजों के दौर में आम हिंदुस्तानियों के लिए खुला ये शहर का पहला क्लब था। इसीलिए इसका नाम रिफह-ए-आम क्लब रखा गया था। रिफा फारसी का शब्द है जिसका मतलब है खुशी और आम यानी हर किसी के लिए। यानी आम लोगों की खुशी। शहर में मौजूद दूसरे क्लब की तरह यहां अंग्रेजी वेशभूषा की अनिवार्यता भी नहीं थी और ना ही किसी को मनाही थी। टेनिस कोर्ट, स्नूकर जैसे कई गेम खेलने से लेकर पढ़ने वालों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी यहां थी। कम अर्से में ही लोकप्रिय हो गए इस क्लब में तमाम सार्वजनिक जलसे होने लगे। इसी जगह को प्रथम विश्वयुद्ध के समय होमरूल लीग के जलसे के लिए चुना गया था, यहीं पर 1920 में सभा करके महात्मा गांधी ने लखनऊ वालों से असहयोग आंदोलन में जुड़ने की अपील की थी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी यहीं हुई थी।

रिफ़ा-ए-आम क्लब ने सन 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक आंदोलन को जन्म दिया और इस तरह साहित्य में क्रांति आई। नारी अधिकारवादी उर्दू लेखिका राशिद जहां ने यहां 9 अप्रैल सन 1936 में प्रगतिशील लेखकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण दिया था। उन्होंने प्रगतिशील लेखन की ज़रुरत के बारे में बताया और लेखकों सेअंग्रेज़ों द्वारा किये जा रहे दमन के बारे में लिखने का आग्रह किया। इस तरह से सयैद सज्जाद ज़हीर और अहमद अली के कुशल नेतृत्व में अंजुमन तरक़्क़ी पसंद मुसन्निफ़िन-ए-हिंद अथवा प्रगतिशील लेखक आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मकसद अभिनव लेखन को बढ़ावा देना था। आंदोलन से सआदत हसन मंटो, इस्मत चुग़ताई, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मुल्क राज आनंद जैसे कई प्रमुख लेखक जुड़ गए।

****

~ज़ेबा हसन

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link : www.mediamap.co.in

Recent Articles

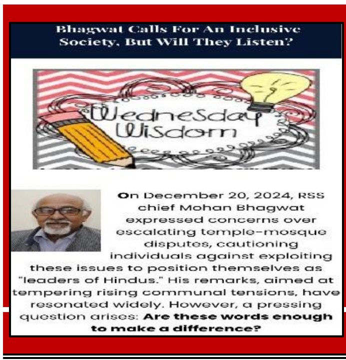
Bhagwat Calls For An Inclusive Society, But Will They Listen?

On December 20, 2024, RSS chief Mohan Bhagwat expressed concerns over escalating temple-mosque disputes, cautioning individuals against exploiting these issues to position themselves as "leaders of Hindus." His remarks, aimed at tempering rising communal tensions, have resonated widely. However, a pressing question arises: **Are these words enough to make a difference?**

Dr Man Mohan Singh : A Lone Warrior Who Unshackled Indian Economy

Gopal Misra
New Delhi | Monday | 30 December 2024
Few in India could have ever imagined that a soft-spoken academic, Dr Man Mohan Singh, would be transforming India, first as a finance minister and later as the Prime

India Keen For Early Improvement In Ties With Dhaka
Prof Shivaji Sarkar
New Delhi | Monday | 16 December 2024
India and Bangladesh have entered a pivotal phase in their diplomatic relationship amidst shifting regional political dynamics. On December 9, Indian

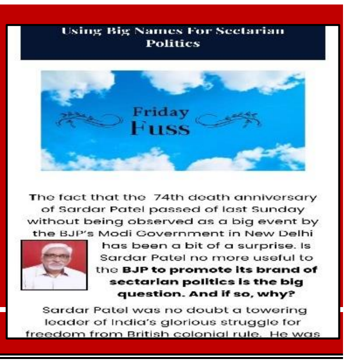
Using Big Names For Sectarian Politics

The fact that the 74th death anniversary of Sardar Patel passed of last Sunday without being observed as a big event by the BJP's Modi Government in New Delhi has been a bit of a surprise. Is Sardar Patel no more useful to the **BJP to promote its brand of sectarian politics is the big question. And if so, why?**
Sardar Patel was no doubt a towering leader of India's glorious struggle for freedom from British colonial rule. He was

View Media Map YouTube

Media Map News

Recent Videos

vol- 1002, 13 jan 25, ep- 59 : महाकुंभ में संत तीर्थयात्री सीवरेज के पानी में नहाने...

vol-1002, 11 jan 25, ep- 58 : महाकुंभ में कई वेशभूषा में बाबा

vol-1002, 9 jan 25, ep-57: मुस्लिम भी इलाहाबाद पुर्ण महाकुंभ में कल्पवास कर...

vol- 1002, 4 jan 2025, ep- 56: Media Map: Youtube meeting

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 42868137378***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक

MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय

फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

Advt.

Please stay with us and explore the beauty of the surrounding areas .

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com